



बहिष्कार कथा बहिष्कार भाजप
जन जन विचार

जन जन की बात जन जन तक

जन जन विचार

साप्ताहिक



WEEKLY TRILINGUAL NEWSPAPER

Language : Hindi, Assamese & English
WEBSITE : www.janjanvichar.in

VOICE OF ALL, FOR ALL

WEEKLY

JAN JAN VICHAR

RNI Regd No. ASMUL/25/A2367::Guwahati, Friday, 21 August 2026 :: Year-1 Vol-32 Issue-11 :: शुक्रवार 21 अगस्त 2026 | शक संवत 1948 | श्रावण | शुक्ल नवमी :: पृष्ठ-20 | मूल्य - 15 रुपये

जन चिंतन

धनेश्वर चौधरी

मातृभाषा की गिनती या अस्मिता की लड़ाई

असम में जनगणना के दौरान मातृभाषा को लेकर उठी बहस महज एक कॉलम में भाषा लिखने का सवाल नहीं है। यह सवाल है- किसकी पहचान दर्ज होगी, किसकी आवाज सुनी जाएगी और आने वाली पीढ़ियों के सामने कौन-सी भाषाएँ जीवित रहेंगी?

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर असम में लंबे समय से बसे उन समुदायों से असमिया को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज करने की अपील की है, जो दूसरे राज्यों से आकर यहां बसे हैं। राजनीतिक तर्क यह है कि इससे असमिया भाषा को मजबूती मिलेगी और बदलते जनसांख्यिकीय परिदृश्य के बीच असमिया भाषियों का प्रतिशत घटने की आशंका का मुकाबला किया जा सकेगा।

शेष पृष्ठ 2 पर

मोदी-हिमंत मंथन : बाढ़ के जखम भरने और 'विकसित असम' बनाने का संकल्प



जन जन विचार

... नई दिल्ली/गुवाहाटी

असम में मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल और भाजपा के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर 20

अगस्त को मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दक्षिण ब्लॉक स्थित सेवा तीर्थ में हुई इस मुलाकात के दौरान असम में हाल की विनाशकारी बाढ़, प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण, लोगों की आजीविका बहाल करने और राज्य के विकास की आगामी रणनीति

हिमंत सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे

पर विस्तार से चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बाढ़ से हुए नुकसान और अब तक चलाए गए राहत एवं पुनर्वास कार्यों की जानकारी देते हुए बाढ़ प्रभावित असम के पुनर्निर्माण की अगली कार्ययोजना से अवगत कराया। प्रधानमंत्री मोदी ने असम की बाढ़ के दौरान केंद्र सरकार की ओर से दिए गए सहयोग को आगे भी जारी रखने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने मुलाकात के बाद कहा कि बाढ़ संकट के दौरान प्रधानमंत्री लगातार स्थिति की समीक्षा करते रहे और हरसंभव सहायता उपलब्ध कराते रहे। उन्होंने कहा कि अब प्राथमिकता बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की पुनर्निर्माण, प्रभावित परिवारों की आजीविका बहाल

शेष पृष्ठ 7 पर

महंगाई ने तोड़ी आम आदमी की कमर

जन जन विचार

... नई दिल्ली/गुवाहाटी

महंगाई के आंकड़े भले ही नियंत्रित दायरे में दिखाई दे रहे हों, लेकिन आम आदमी की रसोई का हिसाब लगातार बिगड़ रहा है। जुलाई 2026 में देश की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.45 प्रतिशत पहुंच गई, जबकि जून में यह 4.38 प्रतिशत थी। खाद्य महंगाई इससे भी अधिक 5.52 प्रतिशत रही। यानी परिवार की सबसे जरूरी जरूरत-खाना-महंगाई के दबाव से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है।

महंगाई का असर केवल बाजार की कीमतों में नहीं दिखता। इसका सीधा असर परिवार के मासिक बजट पर पड़ता है। सब्जी, दाल, तेल, मसाले, दूध, बच्चों की पढ़ाई, परिवहन और रोजमर्रा की दूसरी जरूरतों के खर्च में थोड़ी-थोड़ी वृद्धि मिलकर महीने के अंत में बड़ी रकम बन जाती है। यही वजह है कि महंगाई की वास्तविक पीड़ा

बिगड़ा रसोई का बजट, राज्य सरकार भी चिंतित

जन जन विचार

... गुवाहाटी

असम में खाद्य पदार्थों, फल-सब्जियों और रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने आम परिवारों का घरेलू बजट बिगड़ दिया है। रसोई का खर्च लगातार बढ़ने से मध्यमवर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवारों की चिंता गहराती जा रही है। बाजार में बढ़ती महंगाई और कीमतों को लेकर पैदा हो रही बेचैनी के बीच राज्य सरकार ने अब स्थिति को पड़ताल के लिए कदम उठाया है।

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने 20 अगस्त को उच्चस्तरीय बैठक बुलाई। विभाग के आयुक्त हेमंत भुइयां ने कामरूप चैंबर ऑफ कॉमर्स तथा असम चैंबर ऑफ कॉमर्स के

शेष पृष्ठ 3 पर

खुदरा भाव (गुवाहाटी बाजार)	
सेब	₹ 300 /किलो
केला	₹ 100 /दर्रन
खीनी	₹ 63-64 /किलो
आलू	₹ 30 /किलो
टमाटर	₹ 60 /किलो
प्याज	₹ 45 /किलो
हरी मिर्च	₹ 80 /किलो
धनिया	₹ 40 /गुच्छी

खीनी खुदरा भाव (गुवाहाटी बाजार)	खीनी थोक भाव (गुवाहाटी बाजार)
₹ 63-64 प्रति किलो	₹ 6,100 प्रति बिंदल

और सरकारी आंकड़ों में दर्ज औसत महंगाई के बीच आम उपभोक्ता को बड़ा अंतर महसूस होता है। खाद्य महंगाई बनी सबसे बड़ी चिंता जुलाई में खाद्य कीमतों ने महंगाई के दबाव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रिपोर्टों

के अनुसार प्याज और अदरक जैसी जरूरी वस्तुओं की कीमतों में बहोतीरी ने खाद्य महंगाई को प्रभावित किया। जून में खाद्य महंगाई 5.32 प्रतिशत थी, जो जुलाई में बढ़कर 5.52 प्रतिशत हो गई।

सरकार के मूल्य निगरानी

आंकड़े भी बताते हैं कि कई आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतें ऊंचे स्तर पर हैं। 14 अगस्त के अखिल भारतीय औसत थोक मूल्य आंकड़ों में अरहर दाल करीब 11,407 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द दाल करीब 11,294 रुपए और मूंग

दाल करीब 10,202 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज की गई। पैकड सरसों तेल का औसत थोक मूल्य भी करीब 18,782 रुपए प्रति क्विंटल था।

गांव पर ज्यादा दबाव

महंगाई का बोझ ग्रामीण परिवारों पर शेष पृष्ठ 3 पर

बीएसएनएल का 'फ्रीडम 2.0' ऑफर एक रुपए में 24 दिनों तक मोबाइल सेवा

जन जन विचार
...अंकित मिश्र

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने, डिजिटल सेवाओं का विस्तार करने और देशभर में कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए कई नई ग्राहक-केंद्रित पहल और विशेष ऑफर की घोषणा की। पान बाजार स्थित बीएसएनएल भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में ईवी सेल्स एंड मार्केटिंग के

महाप्रबंधक मनीष राठौड़ ने इसकी जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि बीएसएनएल ने देशभर में तैनाती के लिए 26,300 से अधिक अतिरिक्त 4जी बेस स्टेशन स्टेशन साइटों का ऑर्डर दिया है। इससे कस्बों, गांवों और दूरदराज के क्षेत्रों में नेटवर्क कवरेज का विस्तार होगा। स्वदेशी और 5जी-अपग्रेडेशन तकनीक पर आधारित नेटवर्क से बेहतर काल गुणवत्ता और तेज डेटा सेवाएं मिलने की उम्मीद है।

राठौड़ ने स्वतंत्रता दिवस विशेष 'फ्रीडम 2.0' ऑफर की भी घोषणा की। इसके तहत नए ग्राहक सिर्फ एक रुपए में 24 दिनों की सेवा प्राप्त कर सकेंगे। इसमें प्रतिदिन डेटा, 100 एसएमएस और अनलिमिटेड वॉयस कॉल की सुविधा शामिल है।

प्रेस वार्ता में पीजीएम (सीएफए) सत्येंद्र कुमार डेका, जितेंद्र बहादुर सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। संचालन मीडिया प्रभारी सुमन पाल ने किया।

पृष्ठ 1 का शेषांश...

कराह रही भारत माता

लेकिन यहाँ से एक असहज सवाल पैदा होता है—क्या किसी भाषा को मजबूत करने के लिए दूसरी भाषाओं की पहचान को कमजोर करना जरूरी है?

भाषा किसी सरकारी फॉर्म का महज एक विकल्प नहीं होती। वह घर की आवाज होती है, माँ की लोरी होती है, लोककथा होती है, त्योहारों की स्मृति होती है और पीढ़ियों से चली आ रही सामूहिक पहचान होती है। इसलिए यदि चाय जनजातियों, आदिवासी समुदायों, राजबोंगशी, बंगाली भाषी समाज या किसी अन्य समुदाय को यह आशंका हो कि उनकी मातृभाषा की जगह किसी दूसरी भाषा को दर्ज करने से उनकी अपनी भाषाई पहचान अदृश्य हो जाएगी, तो इस चिंता को खारिज नहीं किया जा सकता।

आदिवासी संगठनों का सवाल बेहद सीधा है—यदि सादरी, कुरुख, मुंडा जैसी भाषाएँ मातृभाषा के रूप में दर्ज ही नहीं होंगी, तो सरकार को उनके वास्तविक भाषाई अस्तित्व और स्थिति का पता कैसे चलेगा? यह सवाल केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि नीति-निर्माण से जुड़ा हुआ है। जनगणना के आंकड़े ही भविष्य की भाषा नीति, शिक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण और सरकारी योजनाओं का आधार बनते हैं।

भाषा बचाने का रास्ता संख्या से होकर जाता है, दबाव से नहीं

असमिया भाषा असम की आत्मा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके संरक्षण और संवर्धन पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन असमिया को मजबूत करने का सबसे टिकाऊ रास्ता यह नहीं हो सकता कि लोग अपनी वास्तविक मातृभाषा छोड़कर असमिया दर्ज करें। मजबूत भाषा वह होती है जिसे लोग स्वेच्छा से सीखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं और अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं।

सरकार यदि वास्तव में असमिया को मजबूत करना चाहती है तो उसे स्कूलों, उच्च शिक्षा, प्रशासन, रोजगार, डिजिटल प्लेटफॉर्म और तकनीक में असमिया की उपयोगिता बढ़ानी होगी। भाषा को सम्मान दीजिए, अवसर दीजिए—सिर्फ आंकड़ा बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए।

दूसरी ओर, आदिवासी और छोटे भाषाई समुदायों की भाषाओं को भी केवल चुनावी भाषणों में याद करना पर्याप्त नहीं होगा। उनकी भाषाओं का संवैधानिक

हो, शिक्षण सामग्री तैयार हो, डिजिटल अभिलेख बनाए जाएँ और जिन भाषाओं के विलुप्त होने का खतरा है, उनके संरक्षण के लिए ठोस नीति बनाई जाए।

असम की ताकत उसकी बहुभाषिकता है

असम को एक भाषा बनाकर मजबूत नहीं किया जा सकता। असम की वास्तविक शक्ति उसकी विविधता में है। असमिया उसकी प्रमुख सांस्कृतिक धारा हो सकती है, लेकिन उसके साथ बोडो, काबी, राभा, मिसिंग, राजबोंगशी, सादरी, कुरुख, मुंडा, बंगाली, हिंदी और अन्य भाषाएँ भी इस भूमि के सामाजिक इतिहास का हिस्सा हैं।

किसी भाषा का सम्मान दूसरी भाषा के अपमान की कीमत पर नहीं होना चाहिए।

जनगणना में मातृभाषा वही दर्ज होनी चाहिए जो व्यक्ति वास्तव में अपनी मातृभाषा मानता और बोलता है। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से असमिया को अपनी मातृभाषा बताता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन किसी समुदाय से यह अपेक्षा करना कि वह अपनी पीढ़ियों पुरानी भाषाई पहचान को छोड़कर दूसरी भाषा अपनाए, एक गंभीर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रश्न खड़ा करता है।

और राजनीतिक दलों को भी यह समझना होगा कि भाषा पहचान की राजनीति का सबसे आसान, लेकिन सबसे खतरनाक हथियार बन सकता है। आज यदि संख्या के लिए एक समुदाय से भाषा बदलने को कहा जाएगा, तो कल दूसरा समुदाय अपनी संख्या और पहचान बचाने के लिए दूसरी भाषा की राजनीति करेगा। फिर असम की सामाजिक एकता का क्या होगा?

असम को भाषाई बहुमत की लड़ाई नहीं, भाषाई न्याय का मॉडल बनना चाहिए।

सरकार का काम यह तय करना नहीं होना चाहिए कि नागरिक अपनी मातृभाषा किसे माँनें। सरकार का काम यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि हर नागरिक अपनी मातृभाषा के साथ सम्मानपूर्वक जाएँ और असमिया सहित दूसरी भाषाएँ सीखने का अवसर पाएँ।

क्योंकि भाषा की रक्षा बंदूक, आदेश या आंकड़ों से नहीं होती—भाषा तब बचती है जब उसकी अगली पीढ़ी उसे गर्व के साथ बोलती है।

असमिया को मजबूत करना है तो उसे दिलों की भाषा बनाइए, सिर्फ जनगणना की संख्या नहीं। और छोटी भाषाओं को मिटाकर बड़ी भाषा कभी महान नहीं बनती।

राशिफल

21 से 27 अगस्त 2026 | विक्रम संवत् 2083-मास : श्रावण, पक्ष : शुक्ल, तिथि : नवमी

मेघ : मेघ राशि वालों के लिए यह सप्ताह कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियाँ और रुके हुए कार्यों में गति लेकर आ सकता है। मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अचानक होने वाले खर्च बजट बिगाड़ सकते हैं। परिवार में पुराने मतभेद बातचीत से सुलझ सकते हैं। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी होगा। थकान और तनाव से बचने के लिए पर्याप्त आराम करें।

वृषभ : वृषभ राशि के जातकों के लिए नौकरी में स्थिरता और व्यापार में नए संपर्क लाभदायक साबित हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं, हालाँकि निवेश में जल्दबाजी से बचना बेहतर होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा और किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव आएगा और अविवाहित लोगों को अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। खान-पान पर नियंत्रण रखें।

मिथुन : मिथुन राशि वालों के लिए नई जिम्मेदारी या नई योजना शुरू करने का अवसर मिल सकता है। पुराने निवेश अथवा अटक हुए भुगतान से लाभ की संभावना है। किसी करीबी व्यक्ति के साथ महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। प्रेम संबंधों में संवाद बेहतर होने से पुरानी गलतफहमियाँ दूर होंगी। मानसिक दबाव कम करने के लिए आराम और मनोरंजन के लिए समय निकालें।

कर्क : कर्क राशि के लिए कार्यक्षेत्र में मेहनत का परिणाम मिलेगा, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करते समय संयम रखना आवश्यक होगा। खर्च बढ़ सकता है, इसलिए अनावश्यक खरीदारी से बचें। परिवार की कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रेम संबंधों में भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ेगी, इसलिए साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। नौद और आराम पर विशेष ध्यान दें।

सिंह : सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ाने वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा और निर्णय क्षमता की सराहना हो सकती है। आय के नए अवसर सामने आ सकते हैं, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचना उचित होगा। परिवार का सहयोग और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन अहंकार को रस्ते के बीच न आने दें। तनाव को हावी न होने दें।

कन्या : कन्या राशि के जातकों के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना विशेष लाभदायक रहेगा। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने से फायदा होगा और पुराने भुगतान मिलने की संभावना है। प्रेम संबंधों में किसी सदस्य से अच्छी खबर मिल सकती है। प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी और अविवाहित लोगों को नया परिचय मिल सकता है।

तुला : तुला राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र में प्रतिभा की सराहना हो सकती है और नया संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित होगा। आय अच्छी रहेगी, लेकिन विलासिता और अनावश्यक खर्च से बचना जरूरी है। परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा। प्रेम संबंधों में पुरानी माहौल लौट सकती है। मानसिक तनाव कम करने के लिए छोटी यात्रा या मनोरंजन उपयोगी रहेगा।

वृश्चिक : वृश्चिक राशि के जातकों को महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय जल्दबाजी से बचना चाहिए। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर लिया गया निर्णय लाभ दे सकता है। परिवार के किसी करीबी व्यक्ति के साथ भावनात्मक बातचीत होगी। प्रेम संबंधों में शक और गलतफहमी से बचना जरूरी है। विश्वास बनाए रखना रस्ते के लिए महत्वपूर्ण रहेगा।

धनु : धनु राशि वालों के लिए कामकाज में प्रगति और नई जिम्मेदारी के योग हैं। यात्रा से जुड़े अवसर भी सामने आ सकते हैं। व्यापारियों को नए सौदों से लाभ मिलने की संभावना है। परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा और प्रेम संबंधों में भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं। काम में जल्दबाजी करने से बचें।

मकर : मकर राशि के जातकों को अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी तथा संपत्ति से जुड़ा कोई मामला आगे बढ़ सकता है। परिवार में शांति और सहयोग बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भरोसा और स्पष्टता बढ़ेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

कुंभ : कुंभ राशि वालों के लिए नई योजना पर काम शुरू करने का अवसर मिलेगा। सहकर्मियों के सहयोग से सफलता प्राप्त हो सकती है। आर्थिक मामलों में आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। परिवार में किसी पुराने विवाद का समाधान हो सकता है। प्रेम संबंधों में अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना लाभदायक रहेगा।

मीन : मीन राशि के जातकों के लिए रचनात्मक कार्यों में सफलता के योग हैं। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को नए विकल्प मिल सकते हैं। धन लाभ के अवसर आएँगे, लेकिन किसी को उधार देने में सावधानी बरतें। परिवार के किसी सदस्य का महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा।

सप्ताह के पर्व/त्योहार

23 अगस्त (रविवार) : झुलन यात्रा आरंभ

24 अगस्त (सोमवार) : श्रावण सोमवार व्रत

25 अगस्त (मंगलवार) : भौम प्रदोष व्रत

26 अगस्त (बुधवार) : आखेटक त्रयोदशी

27 अगस्त (गुरुवार) : व्रत पूर्णिमा



● ज्योतिर्विद आचार्य अखिलेश्वर शुक्ल

भाग्योदय : पहला तल्ला, सेंट्रल प्लाजा, एमएस रोड
फैंसी बाजार, गुवाहाटी-781001 मो.-94350 40387

धन दिशा

स्वास्थ्य बीमा : अब जरूरी है, बाद में नहीं

कुछ साल पहले तक लोग कहते थे, 'अभी तो मैं ठीक हूँ, बाद में ले लूंगा।' लेकिन आज जब एक आम बुखार का इलाज भी निजी अस्पताल में 20,000-30,000 रुपए तक पहुँच सकता है, तो यह सोच बहुत महंगी पड़ सकती है। स्वास्थ्य बीमा अब कोई 'अच्छी बात' नहीं - यह जरूरत है।

एक अच्छी खबर भी है। जनवरी 2026 से सरकार ने व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 0 प्रतिशत कर दी है। यानी अब वही कवर पहले से सस्ता मिलेगा। यह वक्त है - अगर अभी तक स्वास्थ्य बीमा नहीं लिया है, तो इस महीने लें।

कितना कवर चाहिए? कम से कम 5 लाख रुपए का फैमिली फ्लोटर प्लान, जो परिवार के सभी सदस्यों को एक ही पॉलिसी में कवर करे। बड़े शहरों में अस्पताल के खर्च को देखते हुए 10 लाख रुपए का कवर और भी बेहतर है।

क्या ध्यान रखें? पॉलिसी खरीदते वक्त 'वेरिफाईड' जरूर देखें - पहले से चली आ रही बीमारियों के लिए कुछ कंपनियाँ 2-4 साल तक क्लेम नहीं देती। कमरे के किराए की सीमा (रूम रेंट कैप) भी जाँचें - सस्ती पॉलिसियों में यह सीमा क्लेम घटा देती है।

आयुष्मान भारत का क्या? सरकार की आयुष्मान भारत योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बेहतरीन है और 5 लाख रुपए तक का कवर देती है। लेकिन जो इसके दायरे में नहीं आते, उनके लिए अपनी निजी पॉलिसी जरूरी है।

एक जरूरी बात - स्वास्थ्य बीमा जब आप स्वस्थ हों तब लें। बीमारी आने के बाद पॉलिसी लेने पर उस बीमारी को कवर नहीं किया जाता। और जितनी कम उम्र में लेंगे, प्रीमियम उतना कम होगा।

पैसे की तंगी में सबसे ज्यादा दर्द तोब होता है, जब इलाज के लिए पैसे न हों। स्वास्थ्य बीमा वह सुरक्षा है जो बीमारी को आर्थिक संकट नहीं बनने देती।

अगले हफ्ते : सोना - निवेश या सजावट? दिवाली से पहले जानने जरूरी बात।

इस कॉलम के लिए आपका कोई सवाल है? हमें भेजिए

-कोमल जैन

पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट, संस्थापक, वेल्थप्लायर्स- मो. 9004510577

बाबा परशुराम गिरि महाराज को 'महंत' की उपाधि

पूर्वोत्तर में सनातन और शैव परंपरा के विस्तार का लक्ष्य

जन जन विचार
... अंकित मिश्र

सनातन धर्म की प्राचीन संन्यासी अखाड़ा परंपरा में एक महत्वपूर्ण अस्थायी जुड़ते हुए बाबा परशुराम गिरि महाराज को 'महंत' की उपाधि से विभूषित किया गया। मानपाड़ा स्थित काल भैरव शिव मंदिर आश्रम परिसर में आयोजित धार्मिक समारोह में श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के शंकराचार्य स्वामी श्री परमात्मानंद गिरि जी महाराज एवं अखाड़े के राष्ट्रीय सचिव रंजीतानंद गिरि महाराज ने वैदिक मंत्रोच्चार, शंखध्वनि और डमरू के नाद के बीच उन्हें यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा।

धार्मिक परंपराओं के अनुसार जलाभिषेक के पश्चात बाबा परशुराम गिरि महाराज को अंगवस्त्र धारण कराया गया और राजतिलक कर महंत पद से अलंकृत किया गया। शंकराचार्य तथा बड़ी संख्या में साधु-संतों की उपस्थिति में चादरपोशी और पट्टाभिषेक की परंपरा के साथ उन्हें अखाड़े की सेवा और धार्मिक दायित्वों की जिम्मेदारी प्रदान की गई।

समाना नहीं, बड़ी जिम्मेदारी

सनातन हिंदू आर्मी के अध्यक्ष दिनेश पारीक ने कहा कि अखाड़ा



परंपरा में 'महंत' की उपाधि केवल सम्मान का प्रतीक नहीं है, बल्कि धर्म, परंपरा और धार्मिक संस्थाओं के संरक्षण, संचालन तथा संवर्धन की बड़ी जिम्मेदारी भी है। चादरपोशी और पट्टाभिषेक के माध्यम से वरिष्ठ संतों के आशीर्वाद के साथ यह दायित्व सौंपा जाता है।

उन्होंने कहा कि बाबा परशुराम गिरि महाराज लंबे समय से सनातन धर्म के संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्पित रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में सनातन संस्कृति, साधु-संत परंपरा, शैव दर्शन और आध्यात्मिक चेतना को मजबूत करने में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है।

महंत के रूप में बाबा परशुराम गिरि महाराज के सामने अब पूर्वोत्तर भारत में सनातन धर्म की

आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं को मजबूत करने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। मंदिरों और आश्रमों की धार्मिक गतिविधियों को सुदृढ़ करने के साथ शैव परंपरा एवं अद्वैत वेदांत के आध्यात्मिक संदेश को जन-जन तक पहुंचाना उनके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल रहेगा।

उल्लेखनीय है कि प्रयागराज कुंभ के अवसर पर बाबा परशुराम गिरि महाराज ने नागा साधु के रूप में दीक्षा ग्रहण की थी।

समारोह में सनातन हिंदू आर्मी के अध्यक्ष दिनेश पारीक, सलाहकार नारायण सिंह नरुका, सचिव सिद्धार्थ पारीक, सम्प्रत मिश्र, रिकू सिंह और सागर मिश्रा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

पृष्ठ 1 का शेरांश...

बिगड़ा रसोई का बजट...

पदाधिकारियों को बैठक में शामिल होने के लिए औपचारिक पत्र भेजा है। व्यापारिक संगठनों से आवश्यक वस्तुओं के मौजूदा स्टॉक, खरीद-बिक्री और कीमतों से संबंधित दस्तावेज साथ लाने को कहा गया है।

चीनी के दाम ने बढ़ाई चिंता

गुवाहाटी के बाजार में इन दिनों सबसे अधिक चर्चा चीनी की कीमतों को लेकर है। स्थानीय बाजार की जानकारी के अनुसार खुदरा बाजार में चीनी 63 से 64 रुपए प्रति किलो तक पहुँच गई है, जबकि थोक बाजार में इसका भाव करीब 6,100 रुपए प्रति क्विंटल बताया जा रहा है। कीमतों में इस तेजी का असर केवल घरों की रसोई तक सीमित नहीं रहेगा। मिठाई, बेकरी, होटल और खानपान कारोबार की लागत भी इससे प्रभावित हो सकती है।

सब्जियों की कीमतों में भी उबाल

चीनी के साथ-साथ अदरक, लहसुन, बीन्स, हरी मिर्च और कई अन्य सब्जियों के दाम भी ऊँचे बने हुए हैं। अलग-अलग बाजारों में कीमतों में अंतर साफ दिखई

देता है। लगातार बारिश, आवक में उतार-चढ़ाव, परिवहन व्यवस्था और स्थानीय उपलब्धता का सीधा असर खुदरा कीमतों पर पड़ रहा है।

देश के अन्य हिस्सों से भी ऐसी ही चिंताजनक खबरें सामने आती रही हैं। अनियमित बारिश ने धनिया, अदरक, लहसुन और प्याज जैसी वस्तुओं की आपूर्ति को प्रभावित किया है। ऐसे में आने वाले दिनों में बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखना जरूरी हो गया है।

बाढ़ के बाद असम की चुनौती और बड़ी

असम के लिए महंगाई की यह स्थिति इसलिए अधिक संवेदनशील है क्योंकि हाल की विनाशकारी बाढ़ ने ऊपरी असम के कई जिलों में कृषि, परिवहन और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुँचाया है। हजारों परिवार प्रभावित हुए हैं। ऐसे में स्थानीय उत्पादन, सड़क संपर्क और आपूर्ति श्रृंखला में आए व्यवधान का असर स्वाभाविक रूप से बाजार तक पहुँच सकता है।

सरकार के सामने अब दोहरी चुनौती है- एक ओर प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की निबंध आपूर्ति सुनिश्चित करना और दूसरी ओर बाजार में अनावश्यक मूल्यवृद्धि,

जमाखोरी तथा कृत्रिम कमी पर रोक लगाना।

महंगाई ने तोड़ी आम...

अपेक्षाकृत अधिक दिखाई दे रहा है। जुलाई में ग्रामीण खुदरा महंगाई 4.84 प्रतिशत रही, जबकि शहरी महंगाई 3.96 प्रतिशत दर्ज की गई। ग्रामीण परिवारों की आय के मुकाबले खाद्य पदार्थों और परिवहन जैसी आवश्यकताओं पर होने वाला खर्च अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कीमतों में मामूली वृद्धि भी उनके घरेलू बजट को प्रभावित कर सकती है।

थोक बाजार में भी दबाव

महंगाई की तस्वीर केवल खुदरा बाजार तक सीमित नहीं है। जुलाई 2026 में थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई 9.78 प्रतिशत रही। हालांकि यह जून के 9.87 प्रतिशत से थोड़ी कम है, लेकिन स्तर अभी भी ऊँचा है। इसका अर्थ है कि उत्पादकों और कारोबारियों की लागत पर भी दबाव बना हुआ है। यदि उत्पादन, परिवहन, पैकेजिंग और ऊर्जा की लागत बढ़ती है, तो उसका कुछ हिस्सा अंततः उपभोक्ता तक पहुँच सकता है।

सवाल 'महंगाई के अनुभव' का

सरकार और केंद्रीय बैंक के लिए 4.45 प्रतिशत की खुदरा महंगाई फिलहाल नियंत्रण सीमा के भीतर है। लेकिन आम परिवार के

लिए सवाल यह नहीं है कि महंगाई 4 प्रतिशत है या 5 प्रतिशत।

सवाल यह है कि महीने की आय से महीने का खर्च निकल क्यों नहीं पा रहा? यदि वेतन या आय सीमित गति से बढ़े और जरूरी वस्तुओं, शिक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य तथा घरेलू खर्च तेजी से बढ़ें, तो आंकड़ों में नियंत्रित महंगाई भी परिवार के लिए भारी साबित हो सकती है।

राहत के लिए क्या जरूरी?

महंगाई पर नियंत्रण के लिए केवल मौद्रिक नीति पर्याप्त नहीं होगी। सरकार को खाद्य आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने, जमाखोरी और कालाबाजारी पर प्रभावी कार्रवाई, किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने तथा परिवहन और भंडारण लागत घटाने पर ध्यान देना होगा।

क्योंकि महंगाई का असली चेहरा किसी आर्थिक रिपोर्ट की तालिका में नहीं, बल्कि उस गृहिणी की रसोई में दिखाई देता है जो महीने के आखिरी सप्ताह में राशन का हिसाब जोड़ते हुए सोचती है- इस बार खर्च इतना बढ़ कैसे गया? जब महंगाई के आंकड़े 'काबू' में हैं, तो आम आदमी की रसोई का बजट लगातार क्यों बिगड़ रहा है?

संपादकीय

पहले भरोसा, फिर जनगणना

मणिपुर में जनगणना से पहले एनआरसी की मांग को महज विरोध या राजनीति कहकर खारिज करना गंभीर भूल होगी। यह सवाल सिर्फ आंकड़ों का नहीं, बल्कि पहचान, जमीन, जनसांख्यिकी और राजनीतिक भविष्य का है।

मणिपुर आज भी हिंसा और विस्थापन के जख्म से उबर नहीं पाया है। हजारों लोग अपने मूल घरों से बाहर हैं। ऐसे समय में होने वाली जनगणना वर्तमान विस्थापित स्थिति को स्थायी जनसांख्यिकीय तस्वीर में बदल सकती है। यही आशंका आज के असंतोष की सबसे बड़ी वजह है। जनगणना जरूरी है, लेकिन उसके आंकड़े केवल सरकारी रजिस्टर में बंद नहीं रहते। वे भविष्य में परिसीमन, आरक्षण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संसाधनों के वितरण को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए सरकार को जनता की चिंता को कानून-व्यवस्था की समस्या बताकर दबाने के बजाय उसका राजनीतिक समाधान तलाशना चाहिए।

लेकिन एनआरसी भी भावनाओं और आरोपों का विषय नहीं बनना चाहिए। कौन वैध नागरिक है, कौन नहीं—इसका फैसला प्रमाण और कानून से होना चाहिए, भीड़ या अफवाह से नहीं। किसी समुदाय को सामूहिक संदेह में डालना भी उतना ही खतरनाक है जितना वास्तविक चिंताओं को दबाना। सबसे बड़ा सवाल मणिपुर के राजनीतिक नेतृत्व से है—जब जनता पहले से चेतावनी दे रही थी, तब संवाद क्यों नहीं हुआ? संकट भड़कने के बाद दिल्ली की दौड़ राजनीतिक सक्रियता हो सकती है, लेकिन संकट रोकना ही असली नेतृत्व है। अब सरकार को टकराव नहीं, तत्काल सर्वदलीय और सर्वसमुदाय संवाद शुरू करना चाहिए। मणिपुर को ऐसी जनगणना चाहिए जो उसकी वास्तविक तस्वीर दिखाए—विस्थापन से बनी अस्थायी तस्वीर नहीं। पहले भरोसा कायम हो, फिर आंकड़े गिने जाएं।

वंदे मातरम : राष्ट्रभावना को संकीर्ण सोच का बंधक न बनाएं

‘वंदे मातरम्’ पर शर्मिला टैगोर की टिप्पणी और कंगना रनौत की तीखी प्रतिक्रिया ने एक गंभीर सवाल खड़ा किया है—क्या राष्ट्रभावना को भी धार्मिक चरम से देखा जाएगा?

‘वंदे मातरम्’ केवल एक गीत नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की चेतना और मातृभूमि के प्रति समर्पण का ऐतिहासिक प्रतीक है। इसके साहित्यिक रूपकों को शाब्दिक धार्मिक विवाद में बदलना उस राष्ट्रीय भावना को सीमित करना है, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में करोड़ों भारतीयों को प्रेरित किया। असहमति लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन हर राष्ट्रीय प्रतीक को हिंदू-मुस्लिम बहस में खींचना समाज को बांटने वाली राजनीति को ही मजबूत करता है। दूसरी ओर, आलोचना का जवाब भी व्यक्तिगत कटाक्ष से नहीं, तथ्य और इतिहास के आधार पर दिया जाना चाहिए। भारत की पहचान उसकी विविधता और साझा राष्ट्रभावना है। ‘वंदे मातरम्’ को धर्म की बहस में नहीं, स्वतंत्रता और राष्ट्रपौरव की विरासत के रूप में देखना चाहिए। राष्ट्रप्रेम को संकीर्ण मानसिकता का बंधक बनाना किसी के हित में नहीं है।

‘दिमागी नक्सली’

जन जन विचार

... उमेश चतुर्वेदी

लालकिले की प्राचीर से देश के संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, उस पर एक बार फिर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘21वीं सदी में यह बहुत जरूरी है कि हम दशकों पुरानी उन चुनौतियों को खत्म करें, जिन्होंने देश को पीछे रखा है। नक्सलवाद और माओवाद ने लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। उन्होंने अनगिनत माताओं के युवा बेटों को छीन लिया और देश भर के परिवारों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। लगभग चार दशकों तक, नक्सलवाद ने भारत के बड़े हिस्सों और उसकी आबादी के एक बड़े हिस्से को अपनी गिरफ्त में रखा, बंदूक के दम पर शासन किया और संविधान की धजियां उड़ाई। आज हथियारों वाले नक्सल से बड़ी चुनौती दिमागी नक्सली ज्यादा खतरनाक हैं, इससे देश को बचना होगा।

कभी देश के एक तिहाई हिस्से को लाल गलियारे के रूप में जाना जाता था। कभी माओवादियों और नक्सलियों की समानांतर सत्ता नेपाल से लेकर आंध्र प्रदेश तक समानांतर सत्ता चलती थी। उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों को ‘पशुपति से तिरुपति तक’ के नाम से जाना जाता था। देश का गुहमंत्रालय की कमान संभालने के बाद अमित शाह ने 31 मार्च तक देश को लाल गलियारे से मुक्त कराने का वादा किया था। अमित शाह की दोहरी रणनीति के चलते यह गलियारा अब नक्सली हिंसा और आतंक से मुक्त हो चुका है। इसे संयोग कहें या कुछ और, जिस वक्त लाल किले से प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे थे, उसी वक्त लाल गलियारे वाले उड़ीसा के मलकानगिरी और छत्तीसगढ़ के बस्तर के कई गांवों में पहली बार तिरंगा लहरा रहा था। उन तिरंगों को सलामी देने वालों में वे लोग भी भारतीय संविधान के तहत हासिल पुलिस या होमगार्ड की वर्दी में शामिल थे, जो हाल के दिनों तो इन इलाकों में भारतीय संविधान को नहीं मानते थे, जिनका मानना था कि सत्ता बारूद से निकलती है। अब भी उनके हाथों में बंदूकें हैं, जिनके ट्रिगर पर अब भी उनकी ही उंगलियां हैं, लेकिन अब वे भारतीय संविधान की मर्यादा से बंध चुकी हैं।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस बदलाव को रेखांकित किया है, लेकिन उन्हें आशंका है कि समाज के विशेषकर बौद्धिक वर्ग में जो नक्सलवादी मानस के लोग हैं, उनसे निबटना आसान नहीं है।

वैसे दिमागी नक्सली कोई नए शब्द नहीं है। करीब दशक भर पहले फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री ने इसी तरह अर्बन नक्सली शब्द का इस्तेमाल किया था। तब से वामपंथी हिंसा का विरोधी मानस इन शब्दों का खुलकर प्रयोग करता रहा है। वह मानता रहा है कि देश में जब भी अराजक परिस्थितियां बनती हैं, उसके पीछे अर्बन नक्सलियों की ही सोच काम करती है। कह सकते हैं कि दिमागी नक्सली शब्द ने उन्हीं शब्दों को नई पहचान दे दी है। देश का अधिसंख्य बौद्धिक समाज शायद ही इससे इत्तेफाक रखता हो, लेकिन अतीत में यह वर्ग ‘दबाव समूह’ के रूप में काम करता रहा है। छह अप्रैल 2020 को दंतेवाड़ा में घात लगाकर नक्सलियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 75 और छत्तीसगढ़ पुलिस के एक सवाल को बारूदी सुरंगों से उड़ा दिया था। इस घटना के बाद देश का बड़ा वर्ग सदमे में था। तत्कालीन मनमोहन सरकार ने नक्सलियों को सबक सिखाने के लिए सैनिक कार्रवाई करने की ठान ली थी। उस दौरान भी दिमागी नक्सलियों को विश्वविद्यालयों और दूसरे संस्थानों में चिह्नित करने की प्रक्रिया चली थी। लेकिन शहरों में वामपंथी उग्रवाद के समर्थक लोगों के प्रबल विरोध के चलते मनमोहन सरकार सैनिक कार्रवाई से पीछे हट गई थी। हालांकि इस घटना के तीन साल एक महीने बाद 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ की

झीरम घाटी में घात लगाकर नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तकरीबन समूचे नेतृत्व को उड़ा दिया था।

भुक्तभोगी होने के बावजूद कांग्रेस की अगुवाई वाली केंद्रीय सरकार ने नक्सलियों को नेस्तनाबूद करने के लिए न तो ठोस रणनीति बना सकी और न ही रोक लगाने में कामयाब हुई। वह सिर्फ ‘रोकथाम’ की रणनीति पर चलती रही, लेकिन अमित शाह ने इसे बदलकर ‘पुरी तरह खत्म करने’ की रणनीति को अपनाया। इसके तहत, ‘वामपंथी उग्रवाद’ के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति बनाई गई। देश को नक्सल मुक्त करने के राष्ट्रीय लक्ष्य के तहत संवाद, सुरक्षा और समन्वय पर जोर दिया। खुफिया जानकारी पर आधारित ऑपरेशन किए जाने लगे। केंद्रीय और राज्य बलों के बीच बेहतर तालमेल बनाया गया और जरूरत के हिसाब से वित्तीय मदद के लिए खजाना खोला गया। इसके साथ ही मुख्यधारा में लौटने वाले नक्सलियों के पुनर्वास की व्यवस्था को भी जारी रखा गया। खुफिया जानकारी ही थी, कि बसवराजू, पतिराम मांझी, गणेश उड़के और मिलिंद तेलतुंबड़े जैसे कई बड़े माओवादी नेताओं को सुरक्षा बलों ने घेर कर ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों के लगातार दबाव के चलते छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर आत्मसमर्पण हुए।

इसका असर जल्द दिखने लगा। नक्सली हिंसा में 56

वैसे विपक्षी दलों को एतराज है कि इस बहाने प्रधानमंत्री और उनकी सरकार का विरोध करने वालों को दिमागी नक्सली कहकर किनारे करने की कोशिश होगी।

सुरक्षा और विकास की साझी रणनीति के तहत सुरक्षा अभियानों के साथ-साथ पुलिसिंग, कर्नेक्टिविटी, वित्तीय समावेश और आजीविका में लगातार निवेश किया, गया। इसके तहत 2014 के बाद नक्सली इलाकों में 594 थाने, 408 नए सुरक्षा कैंप और 12,211 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गईं। इससे वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में राज्य की मौजूदगी बढ़ी। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में संचार कर्नेक्टिविटी, बैंकिंग ढांचा, डाकघर, आईटीआई, कौशल विकास केंद्र और पुनर्वास नीतियों का जमकर विस्तार किया गया। इससे आर्थिक अवसर पैदा हुए और पूर्व माओवादी कैडरों को मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रोत्साहन मिला।

लालकिले की प्राचीर से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने इसे अपनी सरकार की उपलब्धि के रूप में गिनाया भी। हाल ही में सफल माने जा रहे काकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में पीछे से वामपंथी उग्रवाद समर्थक ताकतों के हाथ की चर्चाएं रहीं। बीस जुलाई के संसद मार्च के दिन हुई हिंसा के पीछे दिल्ली पुलिस पेशेवर अपराधियों के साथ ही वामपंथी संगठनों के हाथ को भी मान रही है। सरकार का मानना है कि हथियार बंद नक्सलियों को पहचानना और उनका मुकाबला आसान है, बनिस्वत समाज के बीच उनकी जैसी मानसिकता का सामना आसान नहीं है।

वैसे विपक्षी दलों को एतराज है कि इस बहाने प्रधानमंत्री और उनकी सरकार का विरोध करने वालों को दिमागी नक्सली कहकर किनारे करने की कोशिश होगी। उनका तर्क है कि इसके जरिए लोकतंत्र की खासियत ‘लोकतांत्रिक विरोध’ के अधिकार को भी बाधित किया जा सकता है। फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जिस तरह इन शब्दों को लेकर सरकार पर जवाबी हमला बोला है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में ये दोनों शब्द चर्चा में ही नहीं रहेंगे, बल्कि सियासी तापमान को बढ़ाए रखने का बड़ा जरिया होंगे।

वंदे मातरम् पूरा नहीं गाएगी कांग्रेस, सीडब्ल्यूसी में फैसला



जन जन विचार
... नई दिल्ली

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक ने आने वाले दिनों के लिए पार्टी की राजनीतिक रणनीति की एक स्पष्ट तस्वीर सामने रख दी है। राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्', राम मंदिर से जुड़े चंदे के आरोप, पेपर लोक, शिक्षा व्यवस्था, महिला आरक्षण, जातीय जनगणना और अरुणाचल प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। इनमें राम मंदिर चंदे का मुद्दा पार्टी के लिए देशव्यापी राजनीतिक अभियान का आधार बनने जा रहा है।

नई दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरेगे की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में पार्टी ने 'वंदे मातरम्' को लेकर अपने पुराने रुख में कोई बदलाव नहीं किया। कांग्रेस के अनुसार, 1937 में

कार्यसमिति द्वारा लिए गए निर्णय के तहत पार्टी के कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत के पहले दो पद ही गाए जाएंगे। पार्टी का कहना है कि उसका वर्तमान निर्णय उसी ऐतिहासिक प्रस्ताव की निरंतरता है।

हालांकि, 'वंदे मातरम्' को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस पहले से ही संवेदनशील रही है। ऐसे समय में कांग्रेस का पुराने निर्णय पर कायम रहना यह संकेत देता है कि पार्टी इस मुद्दे पर अपने ऐतिहासिक रुख से पीछे हटने के बजाय उसे स्पष्ट रूप से सामने रखना चाहती है।

राम मंदिर चंदे का मुद्दा बनेगा बड़ा राजनीतिक हथियार
सीडब्ल्यूसी बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने राम मंदिर से जुड़े 'चंदा चोरी' के आरोपों को गंभीर विषय बताया। उन्होंने कहा कि यह लोगों की भावनाओं से जुड़ा मामला है और कांग्रेस इसे जमीनी

स्तर तक ले जाएगी।

पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस समितियों को गांव और पंचायत स्तर तक इस मुद्दे को उठाने तथा देशभर में प्रदर्शन आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस की रणनीति स्पष्ट है कि इस मुद्दे को केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित न रखते हुए इसे स्थानीय स्तर पर भी उठाया जाए।

हालांकि, इन आरोपों को लेकर अंतिम निष्कर्ष जांच और संबंधित तथ्यों के आधार पर ही निकाला जा सकता है। राजनीतिक दलों के आरोपों और वास्तविक जांच के निष्कर्षों के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी होगा।

छात्रों और शिक्षा व्यवस्था पर भी फोकस

सीडब्ल्यूसी ने पेपर लोक और इसके खिलाफ हुए छात्र आंदोलनों पर भी चर्चा की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार ने छात्रों के आंदोलनों से उचित तरीके से निपटने के बजाय दमनात्मक रवैया अपनाया।

पार्टी ने शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की दिशा में भी रोडमैप तैयार करने का फैसला किया है। खरेगे ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से शिक्षा विशेषज्ञों के साथ मिलकर रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। राहुल गांधी के 'छात्रों की गुंज' कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है और पार्टी के मुताबिक इसे करीब 800 शहरों तक ले जाने की योजना है।

जातीय जनगणना पर भी सरकार को घेरने की तैयारी

जातीय जनगणना की प्रस्तावली में अलग ओबीसी कॉलम नहीं होने को लेकर कांग्रेस ने सरकार से जवाब मांगा है। वेणुगोपाल ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताते हुए कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को फिर उठाएगी।

यह मुद्दा कांग्रेस की व्यापक सामाजिक न्याय की राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। पार्टी का तर्क है कि यदि जातीय जनगणना का उद्देश्य समाज की वास्तविक सामाजिक संरचना को समझना है तो उसमें पिछड़े वर्गों से संबंधित आंकड़ों को स्पष्ट रूप से दर्ज करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

महिला आरक्षण और अरुणाचल का मुद्दा भी एजेंडे में

महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने अपनी मांग दोहराई है कि इसे लोकसभा की वर्तमान 543 सीटों के आधार पर लागू किया जाना चाहिए। वहीं अरुणाचल प्रदेश से जुड़े सीमा और कथित चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर भी कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और

अपनी राजनीतिक मुहिम जारी रखने का संकेत दिया।

बैठक में उत्तराखंड में कांग्रेस अध्यक्ष खरेगे के कार्यक्रम के बाद कथित 'शुद्धीकरण' के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग की।

88 नेताओं की मौजूदगी, विपक्ष की रणनीति पर महामंथन

कांग्रेस के अनुसार, सीडब्ल्यूसी बैठक में 88 नेताओं ने हिस्सा लिया और 33 नेताओं ने चर्चा में अपने विचार रखे। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष खरेगे के साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्वा, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कांग्रेस शासित राज्यों के प्रमुख नेता भी बैठक में शामिल हुए।

कुल मिलाकर सीडब्ल्यूसी की बैठक से कांग्रेस ने यह संकेत दिया है कि आने वाले समय में वह सरकार को कई मोर्चों पर घेरने की तैयारी में है। राम मंदिर चंदे का मुद्दा, शिक्षा और पेपर लोक, जातीय जनगणना, महिला आरक्षण और सीमा सुरक्षा जैसे विषय पार्टी के राजनीतिक अभियान के प्रमुख आधार बन सकते हैं। अब सवाल यह है कि कांग्रेस की यह रणनीति जमीन पर कितना असर पैदा करती है। खासकर राम मंदिर जैसे संवेदनशील धार्मिक मुद्दे को लेकर देशव्यापी आंदोलन का फैसला राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद से लेकर गांव की चौपाल तक किस तरह की राजनीतिक गर्मी पैदा करता है, इस पर पूरे देश की नजर रहेगी।

शिलांग में एजी कार्यालय और क्षेत्रीय क्षमता निर्माण संस्थान ने मनाया 80वां स्वतंत्रता दिवस

जन जन विचार
... शिलांग

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), मेघालय, शिलांग तथा क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, शिलांग के संयुक्त तत्वावधान में 15 अगस्त को 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया।

समारोह की शुरुआत विभिन्न परिसरों में राष्ट्रध्वज फहराने के साथ हुई। लेखापरीक्षा एवं लेखा संपदा, मोतीनगर में सुबह 8 बजे उप महालेखाकार बिनोद भुजेल ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद



लिंडहर्स्ट एस्टेट, लाईटमखड़ा में वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन) धनलक्ष्मी चौरसिया ने राष्ट्रध्वज

फहराया। प्रधान महालेखाकार कार्यालय परिसर में सुबह 8.30 बजे लहुंखोथांग हंगसिंग ने तथा क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान के परिसर में सुबह 9 बजे महानिदेशक लहुंखोथांग हंगसिंग ने ध्वजारोहण किया।

कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रध्वज को सलामी और राष्ट्रगान के साथ हुई।

कार्यक्रम का समापन वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी एसएसडी. सिएम के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। समारोह में दोनों संस्थानों के अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिवारजन उपस्थित रहे।

क्या कांग्रेस अब राष्ट्र से ऊपर हो गई : भाजपा

नई दिल्ली। वंदे मातरम् को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक टकराव और तेज होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस कार्यसमिति ने 1937 के अपने पुराने फैसले को बरकरार रखते हुए पार्टी के कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत के केवल पहले दो अंतरे गाने का निर्णय लिया है। कांग्रेस के इस फैसले पर भाजपा ने तीखा हमला बोलते हुए सवाल उठाया है कि क्या कांग्रेस के लिए अब पार्टी का फैसला राष्ट्र से भी ऊपर हो गया है।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी



अपने राजनीतिक प्रस्ताव को संविधान, संसद और देश से ऊपर रख रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस कांग्रेस ने स्वतंत्रता अब पार्टी का फैसला राष्ट्र से भी ऊपर हो गया है।

भारत में भक्ति : भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप

जन जन विचार

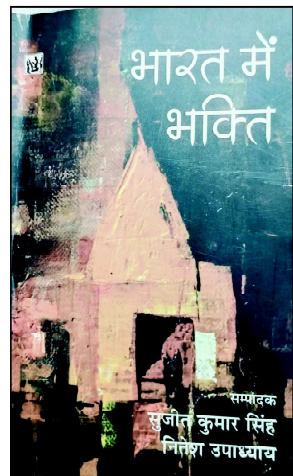


...डॉ मुकेश कुमार

संस्कृत की 'भज' धातु में 'क्ति' प्रत्यय के योग से निष्पन्न 'भक्ति' शब्द केवल ईश्वर के प्रति अगाध अनुरक्ति या आत्मसमर्पण का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह मानवीय संवेदनाओं के विस्तार और सामाजिक चेतना का एक वृहद माध्यम भी है। शाब्दिक अर्थ में 'सेवा' से जुड़ा यह भाव मध्यकाल तक आते-आते एक ऐसे व्यापक लोक-आंदोलन का रूप ले लेता है, जिसने संपूर्ण भारतवर्ष को सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक स्तर पर एक सूत्र में पिरोने का अभूतपूर्व कार्य किया। भक्ति वास्तव में स्वयं को निःशेष भाव से ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना है। विभिन्न विद्वानों ने भक्ति आंदोलन को भिन्न-भिन्न दृष्टियों से रेखांकित किया है; जहां जॉर्ज ग्रियर्सन इसे धार्मिक पुनर्जागरण की संज्ञा देते हैं, वहीं पंडित हजारीप्रसाद द्विवेदी और डॉ. रामविलास शर्मा इसे व्यापक 'लोक-जागरण' से जोड़कर देखते हैं। इसी क्रम में आलोचक मैनेजर पांडेय भक्ति को मूलतः 'प्रेम' की संज्ञा देते हैं। भक्ति हमें 'सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय', समन्वयवादी चेतना, गुरु की महत्ता, सामाजिक समानता और पाखंड के विरोध का पाठ पढ़ाती है। संक्षेप में कहें तो यह एक सच्चा मनुष्य होने की परिभाषा सिखाती है। इसी वैचारिक और सामाजिक चेतना को गहराई से विश्लेषित करती है सुजीत कुमार सिंह और नितेश उपाध्याय द्वारा संपादित तथा लोकभारती प्रकाशन, प्रयागराज से प्रकाशित दो सौ चालीस पृष्ठों की महत्त्वपूर्ण कृति 'भारत में भक्ति'। यह पुस्तक मुख्यतः दो सुविचारित खंडों में विभाजित है। पहला खंड 'भक्ति साहित्य : सैद्धांतिकी' भक्ति आंदोलन की दार्शनिक, सामाजिक और मूल्यगत पृष्ठभूमि पर विस्तार से प्रकाश डालता है, जिसमें कुल ग्यारह गहन आलेख शामिल हैं। भरत प्रसाद, श्रद्धा सिंह, किरण तिवारी, चितरंजन कुमार, सुजीत कुमार सिंह, अमनीश चंद्र पांडेय, अभिषेक कुमार सिंह, अमनीश पांडेय, अमितेश कुमार, शिवप्रसाद शुक्ल और विनय सेन सिंह जैसे मूर्धन्य विद्वानों के लेखों के माध्यम से इस खंड में भक्ति आंदोलन के सैद्धांतिक एवं वैचारिक आयामों को खंगाला गया है। पुस्तक के संपादकीय में सुजीत कुमार सिंह जी अत्यंत यथार्थपरक टिप्पणी करते हैं कि साहित्य मनुष्य की संवेदनशीलता का परिष्कार एवं मानवीय विवेक का विकास करने वाला प्रमुख कला माध्यम है। अखिल भारतीय लोक-जागरण को स्वर देने वाले

मध्यकालीन भक्ति साहित्य में कई प्रगतिशील परंपराएं विकसित होती हैं। अब मेरे दिमाग में कुछ प्रश्न पैदा हो रहे हैं? जब मध्यकालीन भक्ति साहित्य ने कबीर, तुलसी और मीरा जैसे कवियों के माध्यम से लोक-जागरण, करुणा और मानवीय विवेक का विकास किया, तो आज डिजिटल और सूचना-क्रांति के 21वीं सदी के दौर में मनुष्य की वह संवेदना कहां लुप्त हो गई है? क्या आधुनिक तकनीक ने हमें जोड़ने के बजाय मानसिक और भावनात्मक रूप से एक-दूसरे से और अधिक दूर कर दिया है?

दूसरा प्रश्न यह है कि यदि साहित्य मनुष्य के विवेक का परिष्कार करता है, तो 21वीं सदी का शिक्षित और भौतिक रूप से



पुस्तक : भारत में भक्ति

:: संपादक ::

सुजीत कुमार सिंह

नितेश उपाध्याय

:: प्रकाशक ::

लोकभारती प्रकाशन, प्रयागराज

प्रथम संस्करण 2024

मूल्य रु. 250 मात्र

समृद्ध मनुष्य साहित्य और मानवीय मूल्यों से इतना कट क्यों गया है? क्या आज का समाज साहित्य को जीवन जीने का माध्यम मानने के बजाय केवल एक अकादमिक (पढ़ाई-लिखाई का) विषय बनकर रह जाने दे रहा है? साहित्य के अध्येता को यह सोचना चाहिए? इसी भावधारा को आगे बढ़ाते हुए भक्तिकालीन कविता में लोकधर्म के लेखक चितरंजन कुमार लिखते हैं कि यह काव्यधारा एक ऐसे समतामूलक समाज की कल्पना करती है जहां धार्मिक रूढ़ियों, परंपरागत अधविश्वासों, जातिगत, वर्णगत एवं संप्रदायगत भेदभावों और नाना प्रकार के कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं है। उनके अनुसार जो समाज अपने अनुभवों और

संवेदनाओं में ईमानदार है, श्रमशील है तथा सद्गति का साधक है, वही समाज इन संतों के लिए काम्य है।

पुस्तक का दूसरा खंड 'भक्ति साहित्य : अखिल भारतीय स्वरूप' भक्ति आंदोलन की भौगोलिक व्यापकता और क्षेत्रीय विविधताओं के अंतर-संबंधों को सौंदर्य के साथ उजागर करता है। इस खंड के दस आलेखों में देश के भिन्न-भिन्न अंचलों में संत-परंपराओं को समेटा गया है। प्रभाकर सिंह, नयना डेलीवाला, गाजुला राजू, संतोष तांदले, अमरेंद्र त्रिपाठी, रामगोपाल सिंह जादौन, सरोज सिंह, बरिलाल जैन और हरीश कुमार शर्मा जैसे विद्वानों के आलेख यह सिद्ध करते हैं कि द्रविड़ भूमि से उपजी यह भक्ति-धारा किस प्रकार पूरे भारत में फैली। उत्तर भारत में कबीर, रैदास, धना मलूकदास; राजस्थान में मीरा, दादू, रज्जब; गुजरात में नरसी मेहता, महाराष्ट्र में नामदेव, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम; दक्षिण भारत में नौ आलवार, तरेसठ नयनार, पुरंदरदास, अक्का महादेवी; असम में शंकरदेव; बंगाल में जयदेव तथा चैतन्य महाप्रभु; ओडिशा में चंडीदास; कश्मीर में ललहद; बिहार में संत धरणी व दरिया साहब और मध्यप्रदेश में संत सिंगा जी तक यह भक्ति-गंगा अविरल प्रवाहित होती रही। विशेष रूप से दूसरे खंड में प्रभाकर सिंह जी अपने आलेख 'सिर साटै रख रहे, तो भी सस्तो जाण' में जांभाणी साहित्य का अत्यंत प्रासंगिक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। वे दर्शाते हैं कि जांभाणी साहित्य में निर्गुण ज्ञान परंपरा, सूफी मत की प्रेम परंपरा, कृष्णभक्ति शाखा की पशुपालन संस्कृति और रामभक्ति शाखा की मर्यादा तथा नैतिकता का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। इस परंपरा के अनुसार सृष्टि में रहने वाले समस्त जीव-जंतु, पशु-पक्षी और पेड़-पौधे मनुष्य के सहचर हैं। इनसे प्रेम करना और इनकी संवेदना का ध्यान रखना ही सच्ची भक्ति है। आज के उपभोक्तावादी और पर्यावरण-संकट के दौर में जांभाणी साहित्य में निहित प्रेम, पर्यावरण शिक्षा और भक्ति की सामाजिक-सांस्कृतिक चेतना को नए सिरे से पढ़ना और विश्लेषित करना बेहद प्रासंगिक हो जाता है।

अतः 'भारत में भक्ति' पुस्तक भक्ति आंदोलन के सामाजिक-सांस्कृतिक और पर्यावरणीय पहलुओं को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बेहद सरल, रोचक और विश्लेषणात्मक ढंग से प्रस्तुत करती है। संपादकों का यह प्रयास भक्ति साहित्य के विविध रूपों को एक सूत्र में पिरोने में पूरी तरह सफल रहा है। यह कृति न केवल शोधार्थियों और आलोचकों के लिए, बल्कि साहित्य के सामान्य पाठकों के लिए भी एक अत्यंत उपयोगी, दिशा-दर्शक और संग्रहणीय दस्तावेज सिद्ध होती है। यह पुस्तक निस्संदेह पठनीय एवं विचारणीय है। इस सारगर्भित एवं उपयोगी कार्य के संपादन के लिए सुजीत कुमार सिंह और नितेश उपाध्याय बधाई के पात्र हैं।

क्या 'जेन-जी' होना सुरक्षा नियम तोड़ने का लाइसेंस है

कारगिल सेक्टर के एक

संवेदनशील हाई-एल्टीट्यूड चेक पोस्ट पर पर्यटकों और सुरक्षा जवानों के बीच बहस का वायरल वीडियो कई गंभीर सवाल खड़े करता है। बताया जा रहा है कि पर्यटकों को प्रतिबंधित दिशा में आगे बढ़ने से रोका गया था, जहां सुरक्षा नियम और आवश्यक अनुमति लागू थी। वीडियो में एक महिला स्वयं को जेन-जी बताते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती दिखाई देती है।

सवाल सीधा है-क्या किसी पीढ़ी की पहचान राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल से ऊपर हो सकती है? बिल्कुल नहीं। जेन-जी होना न कोई विशेषाधिकार है और न ही सुरक्षा नियमों को चुनौती देने का लाइसेंस।

कारगिल और नियंत्रण रेखा से सटे क्षेत्र सामान्य पर्यटन स्थल नहीं हैं। यहां सैन्य गतिविधियां, मौसम, दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां और सुरक्षा चुनौतियां हमेशा मौजूद रहती हैं। किसी रास्ते को बंद करना, आवाजाही नियंत्रित करना या अनुमति मांगना पर्यटकों को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी और देश की सुरक्षा के लिए होता है। सुरक्षा बल कई बार ऐसे कारणों से निर्णय लेते हैं जिन्हें सार्वजनिक करना भी संभव नहीं होता।

लंबी दूरी तय करके आना किसी प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश का अधिकारपत्र नहीं है। यदि परमिट जरूरी है तो उसकी जानकारी लेना और नियमों का पालन करना पर्यटक की ज़िम्मेदारी है। लोकतंत्र सवाल पूछने का अधिकार देता है, लेकिन संवेदनशील सैन्य चौकी पर सुरक्षा आदेशों से बहस कर उन्हें बदलवाने का अधिकार नहीं।

सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह और व्यक्तिगत सुविधा को राष्ट्रीय सुरक्षा से ऊपर रखना बेहद चिंताजनक प्रवृत्ति है। जवान सीमा पर इसलिए खड़ा है ताकि नागरिक सुरक्षित रहें और देश की सीमाएं सुरक्षित रहें। उसे सम्मान और सहयोग मिलना चाहिए, टकराव नहीं।

यह संदेश केवल एक पर्यटक के लिए नहीं, बल्कि हर नागरिक के लिए है-सीमा पर सुविधा नहीं, सुरक्षा सर्वोच्च होती है। जेन-जी हो या कोई भी पीढ़ी, वर्दी का सम्मान कीजिए, नियमों का पालन कीजिए और याद रखिए कि जवान आपकी आजादी रोकने के लिए नहीं, आपकी आजादी की रक्षा के लिए वहां खड़ा है।

इंग्लैंड को गोल के लिए तरसाया, भारत की बेटियां विश्व कप के अगले दौर में

जन जन विचार
...६ एम्सटेलवीन

भारतीय महिला हॉकी टीम ने एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप में शानदार जुझारूपन दिखाते हुए इंग्लैंड को 0-0 की बराबरी पर रोककर टूर्नामेंट के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया। पूल-डी के इस रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड ने लगातार दबाव बनाया और कई पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए, लेकिन भारतीय रक्षार्पित और गोलकीपिंग के आगे उसकी एक नहीं चली।

भारत को शुरुआत में गोल करने के कई मौके मिले, लेकिन फिनिशिंग में कमी के कारण बढ़त नहीं बन सकी। इसके बाद इंग्लैंड



ने आक्रामक रुख अपनाया और अंतिम चरण में भारतीय गोल पर लगातार हमले किए।

भारतीय गोलकीपर बिचु देवी खरिबाम ने निर्णायक मौकों पर शानदार बचाव करते हुए

इंग्लैंड की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

भारत ने पूरे मुकाबले में अनुशासित रक्षा का परिचय दिया। इंग्लैंड के लगातार पेनल्टी कॉर्नरों के बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने गोल नहीं होने दिया। इस एक अंक के साथ भारत ने पूल-डी में दूसरे स्थान पर रहते हुए अगले दौर में जगह पक्की की, जबकि चीन शीर्ष पर रहा।

यह परिणाम भारतीय महिला हॉकी के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है। अब अगले दौर में टीम को अपनी आक्रामक क्षमता और गोल करने के मौकों को भुनाने पर विशेष ध्यान देना होगा। रक्षा ने रास्ता खोल दिया है, अब बेटियों से गोलों की बरसात की उम्मीद है।

वर्ल्ड कप 2027 के लिए रॉबिन उथप्पा की 'ड्रीम टीम इंडिया'

जन जन विचार
...६ नई दिल्ली

वर्ल्ड कप 2027 के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड को लेकर अभी से ही चर्चा शुरू हो गई है। लगातार ये बहस बनी हुई है कि विश्व कप की टीम में किन खिलाड़ियों को जगह मिलनी चाहिए। दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि, भारत के पूर्व बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने वर्ल्ड कप 2027 के लिए अपनी टीम चुनी है।

उथप्पा ने अपनी टीम में रोहित शर्मा को भी जगह दी है, जिनको लेकर हाल ही में रिपोर्ट्स आई थी कि इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेला गया वनडे मैच उनके करियर का आखिरी मैच हो सकता है। पूर्व भारतीय दिग्गज ने अपनी टीम में कुछ हैरान करने वाले नाम शामिल किए हैं, जिसमें

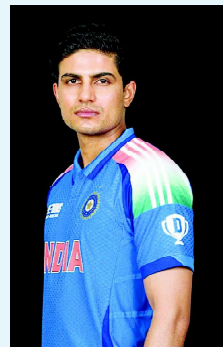


15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का नाम भी शामिल है।

रॉबिन उथप्पा ने तीन चौकाने वाले नाम किए शामिल उथप्पा ने तीन ऐसे खिलाड़ियों को अपनी विश्व कप की टीम में शामिल किया है, जो वर्तमान में



वनडे सेटअप का हिस्सा नहीं हैं। रॉबिन ने 15 साल की उम्र में सनसनी मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी को अपनी टीम में शामिल किया है। वैभव ने भारत के लिए टी20 क्रिकेट, तो खेल लिया है लेकिन अब तक वनडे टीम में उनका नाम एक बार भी



नहीं आया है। सूर्यवंशी के अलावा उथप्पा ने संजू सैमसन को शामिल किया है।

संजू ने भारत के लिए अब तक 16 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 56.67 की औसत के साथ 510 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक भी निकला

है। हालांकि, वे लंबे समय से वनडे टीम का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने आखिरी बार भारत के लिए इस फॉर्मेट में 2023 में खेला था। उथप्पा ने अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को भी अपनी टीम में शामिल किया है। उन्होंने भी भारत के लिए आखिरी बार कोई मैच 4 साल पहले यानी 2022 में खेला था।

रॉबिन उथप्पा की ड्रीम टीम

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन (विकेटकीपर), के.एल.राहुल (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह।

पृष्ठ 1 का शेपांश...

मोदी-हिमंत मंथन : बाढ़ के... करना और समग्र पुनर्वास सुनिश्चित करना है।

1,000 करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है नुकसान

असम में इस वर्ष आई भीषण बाढ़ ने विशेष रूप से ऊपरी असम के कई क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई है। अब तक बाढ़ में कम से कम 105 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें अकेले शिवसागर जिले में 54 मौतें शामिल हैं। पानी उतरने के बाद भी हजारों परिवारों के सामने घर और आजीविका दोबारा खड़ी करने की चुनौती बनी हुई है।

सरकार द्वारा अब तक किए गए आकलन के अनुसार 26,681 मकानों और 18,887 पशुशालाओं को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 41 हजार से अधिक करघों से जुड़े कच्चे माल और 5,98,691 पशुधन के नुकसान का भी आकलन किया गया है। अब तक प्रत्यक्ष नुकसान करीब 480 करोड़ रुपए आंका गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह आकलन अभी प्रभावित आबादी के लगभग 30 प्रतिशत हिस्से तक ही हुआ है। इसलिए अंतिम नुकसान का आंकड़ा 1,000 करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है।

नुकसान का आंकड़ा सार्वजनिक होगा सरकार ने राहत और पुनर्वास प्रक्रिया को

अधिक पारदर्शी बनाने के लिए बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन की सूची सार्वजनिक करने का निर्णय लिया है। इसके लिए एक समर्पित वेब पोर्टल के माध्यम से प्रभावित नागरिक यह जांच सकेंगे कि उनके नुकसान का सरकारी रिकॉर्ड में उल्लेख हुआ है या नहीं।

विकास के एजेंडे पर भी चर्चा

प्रधानमंत्री के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने सरकार के पहले 100 दिनों में शुरू की गई प्रमुख पहलों की जानकारी भी दी। चर्चा में राज्य में आर्थिक विकास को गति देने, आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने और युवाओं तथा आम नागरिकों के लिए नए अवसर पैदा करने जैसे विषय शामिल रहे।

मुख्यमंत्री ने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों को 'विकसित असम' के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास और जनकल्याण की योजनाओं को और तेज गति देना तथा असम को नई विकास ऊंचाइयों तक पहुंचाना है।

अब चुनौती राहत से आगे बढ़कर पुनर्निर्माण की है। बाढ़ से तबाह घरों, खेतों, पशुधन और आजीविका को फिर से खड़ा करना असम सरकार के सामने सबसे बड़ी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री का आश्वासन और केंद्र का सहयोग इस पुनर्निर्माण अभियान को नई गति देने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

‘गटर’ से ‘बेडरूम’ तक पहुंची बयानबाजी

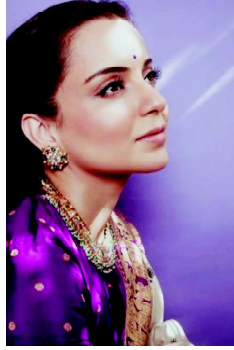
कंगना और रामदेव के बीच बढ़ी तल्लू, सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा पर उठे सवाल

जन जन विचार
... नई दिल्ली

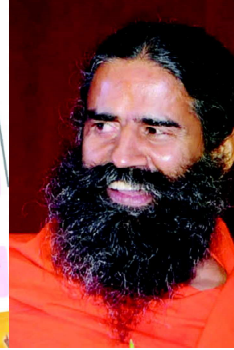
सार्वजनिक जीवन में शब्दों की ताकत जितनी बड़ी होती है, उनकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है। अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत तथा योगगुरु बाबा रामदेव के बीच हालिया बयानबाजी इसका एक ताजा उदाहरण है। युवा पीढ़ी और विशेष रूप से जेन-जी को लेकर कंगना की विवादित टिप्पणी से शुरू हुआ मामला अब व्यक्तिगत टिप्पणियों और चरित्र पर सवाल उठाने तक पहुंच गया है।

कंगना ने सोशल मीडिया पर जेन-जी को लेकर अपनी टिप्पणी में ‘गटर जेनरेशन’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस बयान पर फिल्म जगत से लेकर राजनीतिक क्षेत्र तक तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कंगना ने हालांकि अपने बयान पर माफी मांगने के बजाय उसका बचाव किया। उनका तर्क था कि उन्होंने जिस प्रवृत्ति पर सवाल उठाया, उस पर बहस होनी चाहिए।

इसी विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए बाबा रामदेव ने कंगना की टिप्पणी को गलत बताते हुए उनके



Baba Ji don't day dream about my jawani or bedroom, one can only assume based on rumours and gossip at least mujhe kabhi supreme court se fatkar nahi lagi for false/fraud medical efficacy claims based on hard facts not some gossip or assumptions, so don't give me character lessons, tumse toh bahut ziyada behtar hai mera character no fraud detected here



नजरिये और योग्यता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि युवाओं को इस तरह संबोधित करना उचित नहीं है और पार्टी को भी ऐसे बयानों पर संज्ञान लेना चाहिए। रामदेव की टिप्पणी में कंगना के बचपन, जवानी और निजी जीवन का उल्लेख भी आया, जिसने विवाद को एक नए और अधिक व्यक्तिगत स्तर पर पहुंचा दिया।

इसके बाद कंगना ने सोशल मीडिया पर बेहद तीखे शब्दों में जवाब दिया। उन्होंने बाबा रामदेव से कहा कि वे उनकी जवानी या निजी जीवन के बारे में अनुमान

लगाने से बचें और उन्हें चरित्र का पाठ न पढ़ाएं। कंगना ने पतंजलि से जुड़े पुराने विवादों और चिकित्सा संबंधी दावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का भी संदर्भ देते हुए रामदेव पर पलटवार किया।

यहीं से यह विवाद केवल दो सार्वजनिक व्यक्तियों की नोकझोंक नहीं रह जाता। सवाल यह है कि क्या सार्वजनिक बहस में असहमति का जवाब व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी करके दिया जाना चाहिए? और क्या किसी व्यक्ति के विवादित बयान की आलोचना करते समय उसकी निजी ज़िंदगी को चर्चा का

विषय बनाना उचित है?

कंगना की मूल टिप्पणी भी सवालों से परे नहीं है। देश की युवा पीढ़ी को एक व्यापक और अपमानजनक विशेषण से संबोधित करना सामाजिक संवाद को बेहतर नहीं बनाता। जेन-जी के भीतर करोड़ों युवा हैं, जिनकी सोच, परिस्थितियां और जीवन-शैली अलग-अलग हैं। किसी पूरी पीढ़ी को एक ही नजरिये से देखना उतना ही अनुचित है जितना किसी टिप्पणी का विरोध करते हुए व्यक्तिगत हमले पर उतर जाना।

बाबा रामदेव जैसे प्रभावशाली

सार्वजनिक व्यक्तित्व से भी अपेक्षा की जाती है कि वे आलोचना करते समय मुद्दे तक सीमित रहें। इसी तरह एक सांसद और अभिनेत्री के रूप में कंगना रनौत से भी सार्वजनिक भाषा में संयम और जिम्मेदारी की अपेक्षा स्वाभाविक है।

इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं कि कंगना सही हैं या रामदेव, बल्कि यह है कि क्या सार्वजनिक संवाद का स्तर इतना गिरना चाहिए कि विचारों की जगह निजी ज़िंदगी और चरित्र बहस का केंद्र बन जाए?

लोकतंत्र में तीखी असहमति लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन व्यक्तिगत कटाक्ष उसकी गरिमा को कमजोर करते हैं। किसी बयान की आलोचना तथ्यों, तर्कों और विचारों के आधार पर होनी चाहिए। सार्वजनिक व्यक्तित्व जितने प्रभावशाली होते हैं, उनके शब्दों का असर भी उतना ही व्यापक होता है।

इसलिए कंगना-रामदेव विवाद से निकलने वाला बड़ा संदेश यही है-विचारों से असहमति रखिए, लेकिन व्यक्ति की गरिमा और सार्वजनिक संवाद की मर्यादा मत भूलिए।

भोजपुरी बवाल में रिश्तों की कसक : निरहुआ की बात से भावुक हुई आम्रपाली

जन जन विचार
... मनोरंजन डेस्क

भोजपुरी सिनेमा की चर्चित जोड़ी आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह कोई फिल्म या गाना नहीं, बल्कि रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ का एक भावुक कर देने वाला पल है। शो के नए प्रोमो में निरहुआ की एक टिप्पणी आम्रपाली के दिल को इतनी गहराई से लगी कि वह भावुक होकर रोने लगीं। माहौल बिगड़ता देख शो की मेजबान भारती सिंह ने उन्हें संभालने की कोशिश की।

‘भोजपुरी बवाल’ में भोजपुरी सिनेमा के कई लोकप्रिय चेहरे एक साथ नजर आ रहे हैं। आम्रपाली दुबे, निरहुआ, पवन सिंह, काजल राघवानी और रानी चटर्जी जैसे कलाकार शो में अपनी निजी ज़िंदगी, रिश्तों और करियर से जुड़े अनुभव साझा कर रहे हैं। यही बेबाक बातचीत अब शो की सबसे बड़ी ख़ासियत के साथ-साथ विवादों की वजह भी बन रही है।

शो के एक प्रोमो में निरहुआ, भारती सिंह के साथ आम्रपाली के स्वभाव और उनके ‘नखरों’ को लेकर बातचीत करते नजर आते हैं। बातचीत के दौरान कहीं गई उनकी



बात आम्रपाली को पसंद नहीं आती। वह भावुक हो जाती हैं और रोने लगती हैं। प्रोमो के इस दृश्य ने दर्शकों के बीच सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर निरहुआ की कौन-सी बात आम्रपाली को इतनी चोट पहुंचा गई।

हालांकि प्रोमो में पूरे संवाद का संदर्भ सामने नहीं आया है, इसलिए इस भावुक प्रतिक्रिया को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। सोशल मीडिया पर जरूर दर्शक अपने-अपने अनुमान लगा रहे हैं। कुछ लोग इसे दोनों कलाकारों की पुरानी दोस्ती से जोड़कर देख रहे हैं, तो

कुछ इसे रियलिटी शो की स्वाभाविक भावनात्मक स्थिति मान रहे हैं।

आम्रपाली और निरहुआ की जोड़ी भोजपुरी सिनेमा की सबसे चर्चित जोड़ियों में रही है। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और पर्दे पर उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसी वजह से दोनों के रिश्ते को लेकर समय-समय पर तरह-तरह की चर्चाएं भी होती रही हैं। लेकिन आम्रपाली कई मौकों पर स्पष्ट कर चुकी हैं कि निरहुआ उनके सह-कलाकार और करीबी मित्र हैं। शो में भी जब उनसे उनके रिश्ते को लेकर

सवाल किया गया तो उन्होंने निरहुआ को अपना ‘को-एक्टर’ बताया और उनके बच्चों को अपने दोस्तों की तरह बताया।

यही कारण है कि ‘भोजपुरी बवाल’ में दोनों के बीच दिखाई देने वाली भावनाएं दर्शकों के लिए विशेष दिलचस्पी का विषय बन गई हैं। शो में निजी सवालों का सिलसिला लगातार जारी है और कलाकारों से ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, जिनसे उनकी निजी ज़िंदगी के अनछुए पहलू सामने आ रहे हैं।

इसी शो के एक अन्य प्रोमो ने भी खूब चर्चा बटोरी है। पवन सिंह के बारे में जब नई-नई अभिनेत्रियों के साथ काम करने को लेकर टिप्पणी की गई तो आम्रपाली ने भी बेबाक प्रतिक्रिया दी। इस पर पवन सिंह नाराज नजर आए और उन्होंने साफ कहा कि उन्हें इस तरह की बातें पसंद नहीं हैं।

इससे साफ है कि ‘भोजपुरी बवाल’ केवल मनोरंजन का मंच नहीं रह गया है। कलाकारों के बीच पुरानी दोस्ती, मतभेद, निजी अनुभव और रिश्तों को लेकर पूछे जा रहे सवाल शो को लगातार सुर्खियों में बनाए हुए हैं।

आम्रपाली का भावुक होना भी इसी कड़ी का हिस्सा है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी प्रोमो के कुछ सेकंड देखकर कलाकारों के निजी रिश्तों पर फैसला सुनाना उचित नहीं होगा।



ৰাইজৰ কথা ৰাইজৰ মাজলৈ

জেন জেন বিচাৰ

Guwahati, 21 August, 2026 Friday :: শুক্ৰবাৰ, শাওণ, শুক্ল পক্ষ, মৰমী, শকাব্দ ১৯৪৮



শিলঙৰ হিংসাৰ জুইত অসম-মেঘালয় সম্পৰ্ক

জন জন বিচাৰ

...শু শুক্ৰাহাটী

শিলঙত খাছি ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন-ৰ 'ব্লেক ফ্লেগ' বাহক ৰেলীক কেন্দ্ৰ কৰি সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এতিয়া অসম-মেঘালয় সীমান্তলৈকে বিয়পি পৰিছে। অসমীয়াভুক্ত বাহন আৰু যাত্ৰীৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ অভিযোগক কেন্দ্ৰ কৰি দুয়োখন ৰাজ্যৰ মাজত বৃদ্ধি পোৱা উত্তেজনাৰ মাজতে অসম আৰু মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কনৰাড কে. চাংমা ই শান্তি, সংযম আৰু আলোচনাৰ আহ্বান জনাইছে। দুয়োগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক কৰাৰ বাবে দুয়োখন ৰাজ্যৰ মনোনীত কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ মাজত আলোচনাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে।

শিলঙৰ ৰেলীত হিংসা

বাহনত আক্ৰমণ

১৯ আগষ্টত শিলঙত খাছি ছাত্ৰ সন্থা-য়ে নিজৰ পাঁচদফাীয়া দাবীৰ সমৰ্থনত উলিওৱা ক'লা পতাকাৰ বাহক ৰেলী হঠাতে হিংসাত্মক ৰূপ লয়। বিভিন্ন স্থানত বাহনত আক্ৰমণ, শিলঙটী নিৰ্দ্দেহ, ৰাজহুৱা সম্পত্তি ভাঙি-চুৰমাৰ আৰু চৰকাৰী বাহনত অগ্নিসংযোগৰ অভিযোগ উত্থাপন হয়। স্বামী বিবেকানন্দ আৰু নেতাজী সুভাষচন্দ্ৰ বসুৰ প্ৰতিমূৰ্ত্তিও ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ কথা প্ৰকাশ পাইছে। ঘটনাটোৰ আটাইতকৈ উদ্বেগজনক দিশটো হৈছে অসমৰ পঞ্জীয়নভুক্ত বাহন আৰু যাত্ৰীৰ ওপৰত লক্ষ্য কৰি আক্ৰমণ চলোৱাৰ অভিযোগ। অসমীয়া টেক্সি

শান্তিৰ আহ্বান দুই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, মন্ত্ৰী পৰ্যায়ত হ'ব বৈঠক



আৰু বাণিজ্যিক বাহন চালকসকলৰ সংগঠনে এই ঘটনাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰি মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু পৰ্যটন মন্ত্ৰীৰ পৰা ক্ষমা বিচৰা, ক্ষতিগ্ৰস্ত বাহনৰ ক্ষতিপূৰণ আৰু অসমীয়াভুক্ত বাহন তথা চালকৰ নিৰাপত্তাৰ নিশ্চয়তা দাবী কৰিছে। খানাপাৰা—যোৰাবাটত প্ৰতিবাদ, থমকি ৰ'ল মেঘালয়মুখী যাতায়াত শিলঙৰ ঘটনাৰ পিছদিনা অসমত ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া তীব্ৰ হৈ উঠে। ক্ষুদ্ৰ অসমীয়া টেক্সি আৰু বাণিজ্যিক বাহন চালকসকলে খানাপাৰা আৰু যোৰাবাটত মেঘালয়মুখী পথ অৱৰোধ কৰে। ফলত দুয়োখন ৰাজ্যৰ মাজৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ যাতায়াত ব্যৱস্থা বাহত হয় আৰু সাধাৰণ যাত্ৰী, পৰ্যটক তথা ব্যৱসায়ীসকলে সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। এই ঘটনাই এটা কথা পুনৰ স্পষ্ট

কৰি তুলিছে-দুয়োখন ৰাজ্যৰ মাজত থকা আন্তঃৰাজ্যিক সম্পৰ্কত কোনো হিংসাত্মক ঘটনা ঘটিলে তাৰ প্ৰভাৱ কেৱল ৰাজনীতিত সীমাবদ্ধ নাথাকে; সাধাৰণ মানুহৰ যাতায়াত, ব্যৱসায়-বাণিজ্য আৰু জীৱিকাতো তাৰ পোনপটীয়া প্ৰভাৱ পৰে। গ্ৰেপ্তাৰ, নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আৰু পৰ্যটনত শংকা হিংসাৰ ঘটনাৰ পিছত মেঘালয় আৰক্ষীয়ে খাছি ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন-ৰ কেইবাজনো নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ইফালে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ আৰু শান্তি ঘূৰাই অনাৰ বাবে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাও শক্তিশালী কৰা হৈছে। ঘটনাৰ পিছত মেঘালয়ৰ পৰ্যটন খণ্ডতো উদ্বেগ সৃষ্টি হৈছে আৰু পৰ্যটকৰ সুৰক্ষা তথা সহায়ৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে হেল্পলাইন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে।

বিভিন্ন মহলৰ শান্তিৰ আহ্বান

অসমত ঘটনাটোক লৈ বিভিন্ন দল-সংগঠনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা-ৰ সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰণ ফুকনে এই ঘটনাই অসম-মেঘালয়ৰ সম্পৰ্কত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে বুলি আশংকা প্ৰকাশ কৰি হিংসাত জড়িতসকলক চিনাক্ত কৰি আইন অনুসৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে।

অসম জাতীয় পৰিষদ-ৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়েও অসমৰ যাত্ৰী আৰু পৰ্যটকৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে মেঘালয় চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে। আনহাতে, মহিলা কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰে বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ ফলত হোৱা লোকচানৰ দায়িত্ব কোনো ল'ব সেই প্ৰশ্ন

উত্থাপন কৰিছে।

'ভগ্নী ৰাজ্য'ৰ সম্পৰ্কত

বিভাজনৰ বিষ় নহওক

অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাৰ সৈতে হোৱা আলোচনাৰ কথা উল্লেখ কৰি কয় যে অসম আৰু মেঘালয় 'ভগ্নী ৰাজ্য'; যাৰ মাজত গভীৰ ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক আৰু জনসাধাৰণৰ সম্পৰ্ক আছে। তেওঁ দুয়োখন ৰাজ্যৰ মাজত পাৰস্পৰিক সন্মান, সংযম আৰু সংবেদনশীলতা বজাই ৰখাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে।

মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমায়ো ঘটনাটোক 'দুৰ্ভাগ্যজনক হিংসা' বুলি অভিহিত কৰি কয় যে ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়াই দুয়োখন ৰাজ্যৰ সাধাৰণ নাগৰিক আৰু যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ প্ৰভাৱিত কৰিছে। পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক কৰাৰ বাবে দুয়োখন চৰকাৰে একেলগে কাম কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে।

এতিয়া প্ৰশ্ন এটাই-এটা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ হিংসাত্মক পৰিণতিয়ে যেন দশকজোৰা অসম—মেঘালয়ৰ জনসম্পৰ্কত ফাট মেলাব নোৱাৰে। দাবী-দাবা থাকিব পাৰে, মতভেদ থাকিব পাৰে; কিন্তু বাহনত আক্ৰমণ, যাত্ৰীক ভয় দেখুওৱা, ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংস বা প্ৰতিশোধমূলক পথ অৱৰোধ কোনো সমস্যাৰ সমাধান হ'ব নোৱাৰে। দুয়োখন ৰাজ্যৰ চৰকাৰ, ছাত্ৰ সংগঠন আৰু নাগৰিক সমাজে এতিয়া উত্তেজনাৰ পৰিৱৰ্তে সংলাপৰ পথ বাছি লোৱাটোৱেই উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ শান্তি আৰু ভাতৃত্ববোধৰ বাবে সৰ্বাধিক প্ৰয়োজনীয়।

বিভাগীয় দেৱাল ভাঙক, যুৱ সমাজৰ সৈতে সংযোগ বঢ়াওক

জন জন বিচাৰ

...শু নতুন দিল্লী

ভাৰত চৰকাৰৰ কাম-কাজত বিভাগীয় পৃথকীকৰণ বা 'চাইলো' মানসিকতা পৰিহাৰ কৰি সামূহিক চিন্তা, সমন্বয় আৰু দায়িত্ববোধৰে আগবাঢ়িলে জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলক আহ্বান জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৱেন্দ্ৰ মোদীয়ে। বৃহস্পতিবাৰে ৭, লোক কল্যাণ মৰ্গস্থিত বাসভৱনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সচিবসকলৰ সৈতে অনুষ্ঠিত তৃতীয়খন উচ্চস্তৰীয় বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশৰ ভৱিষ্যৎ উন্নয়নৰ বাবে দীৰ্ঘম্যাদী

দৃষ্টিভংগীৰে কাম কৰাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে।

বৈঠকত আন্তঃগাঁথনি আৰু সংযোগ, নিৰাপত্তা আৰু বৈদেশিক পৰিক্ৰমা, সুশাসন, কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা, তথ্য ব্যৱস্থাপনা, যুৱ সমাজৰ অংশগ্ৰহণ, প্ৰতিৰক্ষা গৱেষণা আৰু সামুদ্ৰিক উন্নয়নকে ধৰি বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত চৰকাৰৰ ভৱিষ্যৎ কমিটী সদৰ্ভত বিস্তৃত আলোচনা কৰা হয়।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিভাগসমূহৰ মাজত সমন্বয়ৰ



অভাৱক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে অভিহিত কৰে। তেওঁৰ মতে, 'চাইলো' মানসিকতা কেৱল

প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাৰ সমস্যা নহয়; ই এক মানসিকতাৰ সমস্যাও। সেয়েহে প্ৰতিটো বিভাগে নিজৰ দায়িত্ব

মালিকানা গ্ৰহণ কৰি দেশৰ সামগ্ৰিক স্বার্থক আগত বাধা কাম কৰিব লাগিব।

ক'ভিড-১৯ মহামাৰী আৰু পশ্চিম এছিয়াৰ সংকটৰ সময়ত বিভিন্ন মন্ত্ৰালয় আৰু বিভাগে যি সমৰ্থিতভাৱে কাম কৰিছিল, সেই অভিজ্ঞতাক চৰকাৰৰ স্থায়ী কাৰ্মসংস্কৃতিৰ অংশ কৰি তুলিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনায়।

দেশৰ নীতি নিৰ্ধাৰণত নতুন চিন্তা আৰু উদ্ভাৱনমূলক ধাৰণা অন্তৰ্ভুক্ত

১০ পৃষ্ঠাত

বহাৰ পূব খৰাগাঁৱত বিশেষ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান

জন জন বিচাৰ

...বহা

বহাৰ পূব খৰাগাঁৱৰ সামূহিক মঞ্চত বৃহস্পতিবাৰে এক বিশেষ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। পূব খৰাগাঁও ববৰা-আটি মধুপুৰ ৰঙালী বিহু উদযাপন সমিতি আৰু পূব খৰাগাঁও খেউজ সাধনা শিল্পী সমাজৰ যৌথ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ প্ৰথম স্থান লাভ কৰি অঞ্চলটোৰ গৌৰৱ বৃদ্ধি কৰা জন্মমণি মেধীসহ মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত স্তাৰ আৰু ডিষ্টিন্‌চন লাভ কৰা প্ৰায় ৬০ৰো অধিক কৃতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়।

প্ৰত্যেকগৰাকী কৃতি শিক্ষাৰ্থীক ফুলাম গামোচা আৰু মানপত্ৰ প্ৰদান কৰি তেওঁলোকৰ উজ্জল ভৱিষ্যৎ কামনা কৰা হয়।

প্ৰাক্তন শিক্ষক, সমাজকৰ্মী তথা ধৰ্মপ্ৰাণ ব্যক্তি কিনাবাম বৰদলৈৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটো শিক্ষক, লেখক তথা সমাজকৰ্মী লখীপ্ৰসাদ ডেকাই সঞ্চালনা কৰে।

পৃষ্ঠা ৯ পৰা—

বিভাগীয় দেৱাল...

কৰাৰ বাবে চৰকাৰী বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয় আৰু যুৱ সমাজৰ মাজত অধিক সংলাপ গঢ়ি তোলাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে।

তেওঁ বিষয়াসকলক যুৱ প্ৰজন্মৰ সৈতে অধিক যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ আহ্বান জনাই কয় যে শিক্ষানুষ্ঠান আৰু যুৱসমাজৰ অংশগ্ৰহণে নীতি নিৰ্ধাৰণত বহু নতুন আৰু পৰম্পৰাবহিৰ্ভূত চিন্তাৰ জন্ম দিব পাৰে।

কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ ব্যৱহাৰ, কিন্তু মানৱীয় সিদ্ধান্ত অটুট থাকক

বৈঠকত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-ব ব্যৱহাৰৰ সন্দৰ্ভতো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা আগবঢ়ায়। এআইৰ সম্ভাৱনাক সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি নতুন সমাধান বিকশিত কৰাৰ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে তেওঁ স্পষ্ট কৰে যে প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ সমান্তৰালভাৱে মানৱীয় হস্তক্ষেপ আৰু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষমতা অটুট থাকিব লাগিব।

তেওঁ তথাক দেশৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদ আৰু ভৱিষ্যতৰ শক্তি হিচাপে অভিহিত

মুম্ময় বৰদলৈয়ে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে। অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে খৰাগাঁৱৰ ৰজা তথা সমাজকৰ্মী সমৰ সিংহ ডেকাই সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকা আৰু হাটপুৰ জুৱিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত বক্তিত প্ৰজ্ঞালন কৰে। তনুশ্ৰী বৰদলৈয়ে ‘মাটি আখৰা’ শ্ৰুতীয়া নৃত্য পৰিবেশন কৰে।

অনুষ্ঠানত বহা সমষ্টিৰ বিধায়ক শশীকান্তদাস, বহা মহকুমাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক সোণমণি শইকীয়া, বহা মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ প্ৰবক্তা ডঃ নন্দিতা গোস্বামী, শিক্ষাবিদ মাধৱ মহন্ত, বহা আঞ্চলিক কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সভাপতি হেমকান্ত শইকীয়া, সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ উপদেষ্টা পী কুমাৰ মহন্ত, বহা আঞ্চলিক আছুৰ নেতা সঞ্জয় কুমাৰ কাকতিসহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু স্থানীয় ৰাইজ উপস্থিত থাকে।

অনুষ্ঠানটোৱে কৃতি শিক্ষাৰ্থীসকলক উৎসাহিত কৰাৰ লগতে অঞ্চলটোত শিক্ষা আৰু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত এক ইতিবাচক পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাৰ বাৰ্তা বহু কৰে।

কৰে। বিভিন্ন বিভাগে তথা সংগ্ৰহ, সংৰক্ষণ আৰু ব্যৱস্থাপনাত বিপুল সম্পদ ব্যয় কৰিলেও বিভাগীয় পৃথকীকৰণ আৰু বিচ্ছিন্ন তথা ব্যৱস্থাৰ বাবে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাই বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। সেয়েহে তথ্যৰ আন্তঃকাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধি আৰু বিভাগসমূহৰ মাজত সুৰক্ষিত তথ্য বিনিময়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে।

প্ৰতিৰক্ষা গৱেষণা আৰু উদ্ভাৱনক নতুন গতি
প্ৰতিৰক্ষা ক্ষেত্ৰত গৱেষণা আৰু উদ্ভাৱনক অধিক উৎসাহিত কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথাও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে। ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা উদ্যোগক বিশ্ব পৰ্যায়ত অধিক প্ৰতিযোগিতামূলক কৰি তুলিবলৈ প্ৰতিৰক্ষা শিক্ষা, গৱেষণা আৰু দক্ষ মানৱ সম্পদ বিকাশ শক্তিশালী কৰাৰ ওপৰত তেওঁ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে।

বন্দৰ উন্নয়নৰ পৰা ‘পৰ্ট-লেড ডেভেলপমেণ্ট’লৈ
সামুদ্ৰিক খণ্ডৰ উন্নয়ন সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জাহাজ নিৰ্মাণক ইতিমধ্যে আন্তঃগাঁথনিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি ইয়াৰ অগ্ৰগতি মিছন মোডত পৰ্যালোচনা কৰাৰ আহ্বান জনায়।

কেৱল বন্দৰ উন্নয়নতে

অসমৰ বাবে ১০ হাজাৰ কোটি টকাৰ বিশেষ বান সাহায্য পেকেজ ঘোষণা কৰক : গৌৰৱ গগৈ

জন জন বিচাৰ

...গুৱাহাটী

শেহতীয়া ভয়াৱৰ বানত অসমত ব্যাপক ক্ষতি সাধন হোৱাৰ পৰিৱেশিত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ উপ-নেতা গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক অসমৰ বাবে ১০ হাজাৰ কোটি টকাৰ বিশেষ বান সাহায্য পেকেজ ঘোষণা কৰিবলৈ দাবী জনাইছে।

গগৈয়ে কয় যে বানপানীৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ বহু অঞ্চলত পথ, দোকান-পোহাৰ, বিদ্যালয় আৰু খোৱা পানীৰ আন্তঃগাঁথনি ব্যাপকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। সেয়ে বানপানীত লোকসকলৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষতি পূৰণ আৰু গ্ৰাম্য আন্তঃগাঁথনি পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিশেষ আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়োৱা প্ৰয়োজন।

পিএম কেয়াৰ্ছ ফাণ্ডৰ ভূমিকাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে গগৈয়ে। তেওঁ ফাণ্ডৰ শেহতীয়া অডিট প্ৰতিবেদনৰ উদ্ধৃতি দি দাবী কৰে যে ফাণ্ডটোৰ মুঠ পুঁজি প্ৰায় ৮.৪৫২

সীমাবদ্ধ নাথাকি ‘পৰ্ট-লেড ডেভেলপমেণ্ট’-ৰ দিশত আগবাঢ়িলে তেওঁ নিৰ্দেশ দিয়ে। উৎপাদন উদ্যোগ আৰু ৰপ্তানিমুখী উদ্যোগসমূহৰ সৈতে বন্দৰ আৰু সামুদ্ৰিক আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নত সংযোগ স্থাপনৰ ওপৰতো তেওঁ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে।

জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ বিষয়াৰ মাজত অধিক যোগাযোগৰ আহ্বান

বৈঠকৰ অন্তিম পৰ্যায়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সমগ্ৰ চৰকাৰী ব্যৱস্থাত সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গী, উদ্ভাৱন, সামূহিক দায়িত্ব আৰু দলীয় মানসিকতা শক্তিশালী কৰাৰ আহ্বান জনায়। তেওঁ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলক কনিষ্ঠ বিষয়াসকলৰ সৈতে অধিক অনানুষ্ঠানিক আৰু পোনপটীয়া যোগাযোগ স্থাপন কৰাৰ লগতে বিভিন্ন সেৱা, কেডাৰ আৰু বিভাগৰ মাজত শক্তিশালী পেছাদাৰী নেটৱৰ্ক গঢ়ি তুলিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে।

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাৰ্তা স্পষ্ট-ভৱিষ্যতৰ ভাৱত গঢ়িলে কেৱল বিভাগীয়লক্ষ পৃথক কৰিলেই নহ’ব; সমগ্ৰ চৰকাৰ ব্যৱস্থাই একেটা দল হিচাপে কাম কৰিব লাগিব। যুৱ শক্তি, প্ৰযুক্তি, তথ্য আৰু উদ্ভাৱনক একেলগে লৈ এই সমন্বিত কৰ্মসংস্কৃতিয়েই বিকশিত ভাৰতৰ পথ অধিক সুদৃঢ় কৰিব পাৰে।



কোটি টকা, যাৰ প্ৰায় ৯০ শতাংশ ধন স্থায়ী আমানতত ৰখা হৈছে। গগৈৰ দাবী অনুসৰি, ২০২৪-২৫ বিত্তীয় বৰ্ষত ফাণ্ডটোৰ পৰা মাত্ৰ ৮৭.৮৫ লাখ টকা ব্যয় কৰা হৈছিল। অসমে ভয়াৱৰ বানৰ সন্মুখীন হৈ থকাৰ সময়ত পিএম কেয়াৰ্ছ ফাণ্ডে কিয় ৰাজ্যখনক সহায় নকৰিলে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি গগৈয়ে কয়, “প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সঁচাকৈয়ে অসমৰ কথা চিন্তা কৰেনে?”

তেওঁ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় সাহায্য পুঁজি থকাৰ পিছতো পিএম কেয়াৰ্ছ ফাণ্ডৰ প্ৰয়োজনীয়তা সন্দৰ্ভতো প্ৰশ্ন কৰে। গগৈৰ

অভিযোগ, সংকটৰ সময়ত অসমে বিভিন্ন সংগঠন আৰু ব্যক্তিৰ সহায়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হৈছে।

ইফালে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্যক দুৰ্যোগ সঁহাৰি পুঁজি অধীনত অসমলৈ এতিয়ালৈকে ৩৭৯.৩৫ কোটি টকাৰ প্ৰথম কিস্তি অনুমোদন কৰিছে।

উল্লেখ্য, ১৯ জুলাইৰ পৰা অসমত কেইবাটাও বানৰ টোৱে ব্যাপক ক্ষতি সাধন কৰিছে। শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাটকে ধৰি কেইবাখনো জিলা বানত বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি, এই পৰ্যন্ত বানত ১০৫জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে।

এই সপ্তাহৰ বাৰ্শিফল

২১ আগস্ট, ২০২৬ৰ পৰা ২৭ আগস্ট, ২০২৬লৈ

মেঘ : আধ্যাত্মিক চেতনা বৃদ্ধি। কৰ্মক্ষেত্ৰত সুনাম বৃদ্ধি। বিদ্যাৰ্থীৰ শুভ।

বৃষ : ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভ ফল। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। চেষ্টাৰ সফলতা লাভ।

মিথুন : আৰ্থিক অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। মানসিক উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি। ধৰ্মীয় কাৰ্য্যৰ পৰা লাভ।

কৰ্কট : আনন্দ ফুৰ্তিৰ মাজেৰে সপ্তাহটো পাৰ হ'ব। কৰ্মব্যস্ততা বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে। ব্যয় বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে।

সিংহ : ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰত মনোনিবেশ থাকিব। দৰকাৰী সিদ্ধান্ত সাৱধানে ল'ব। প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ পৰা লাভ।

কন্যা : সপ্তাহটো কিছু পৰিমাণে বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। মানসিক উদ্বিগ্নতা থাকিব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত শুভ।

তুলা : কৰ্মক্ষেত্ৰত সপ্তাহটো শুভ। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ পৰা লাভ। সামাজিক সুখ্যাতি লাভ।

বৃশ্চিক : শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰত সপ্তাহটো শুভ। অদৰকাৰী খং ৰাগ নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা কৰিব। চেষ্টাৰ সফলতা লাভ।

ধনু : আকস্মিক ব্যয় বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে। কৰ্মক্ষেত্ৰত শুভ ফল। শৰীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সচেতন হ'ব।

মকৰ : আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত বাধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। মানসিক উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। আদৰকাৰী বাদ বিবাদৰ পৰা আতৰি থাকক।

কুম্ভ : কৰ্মক্ষেত্ৰত যশস্যা বৃদ্ধি। সামাজিক কাৰ্য্যৰ পৰা লাভ। ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰত মনোনিবেশ থাকিব।

মীন : আধ্যাত্মিক চেতনাৰ দ্বাৰা মানসিক শান্তি বৃদ্ধি। কৰ্মক্ষেত্ৰত শুভ ফল। সামাজিক মান মৰ্যাদা বৃদ্ধি।

-হিতেন শৰ্মা শাস্ত্ৰী

অধ্যাপক, বিশ্ব জ্যোতিষ বিদ্যা পীঠ, অসম শাখা
যোগাযোগ : ৯৮৫৪০২৬৭৭৯

অসম চৰকাৰৰ ১০০ দিন, ১০০ মাইলৰ খুঁটি

জন জন বিচাৰ

...গুৱাহাটী

মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰৰ প্ৰথম ১০০ দিনৰ ১০০টা উল্লেখযোগ্য সাফল্যৰ খতিয়ান দাঙি ধৰিছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। '১০০ দিন, ১০০ মাইলৰ খুঁটি' শীৰ্ষক এই প্ৰতিবেদনত জনকল্যাণ, মহিলা সৰলীকৰণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, আন্তঃগাঁথনি, বিনিয়োগ, প্ৰযুক্তি, পৰিৱেশ সংৰক্ষণ, ক্ৰীড়া আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ বিভিন্ন পদক্ষেপৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে।

মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে, চৰকাৰৰ প্ৰথম ১০০ দিনৰ কাম-কাজৰ মূল লক্ষ্য হৈছে জনকেন্দ্ৰিক শাসন আৰু 'বিকশিত অসম' গঢ়াৰ সংকল্প।

জনকল্যাণমূলক আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত অৰুণাচল ৩.০ পূৰ্ণৰ আৰম্ভ কৰি ৩৭ লাখতকৈ অধিক মহিলাক সামৰি লোৱা হৈছে। নিজুত মইনা আঁচনিৰ অধীনত ৫.১৬ লাখতকৈ অধিক ছাত্ৰী আৰু নিজুত বাবুৰ জৰিয়তে ৯৯ হাজাৰতকৈ অধিক

ছাত্ৰ উপকৃত হৈছে।

কৃষিক্ষেত্ৰত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলক কৃষকৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ লগতে পিএম-কিষাণ আঁচনিৰ অধীনত ৫১.৩৭৩ কোটি টকাৰ সাহায্য বিতৰণ কৰা হৈছে। ২০২৫-২৬ বিপণন বৰ্ষত ৬.৮৮ লাখ মেট্ৰিক টনতকৈ অধিক ধান ক্ৰয় কৰা হৈছে।

আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত ৫৫২ কিলোমিটাৰ পথ আৰু ৪৭খন দলং নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লগতে তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰকল্প আগবঢ়োৱা হৈছে। গুৱাহাটীত শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জী উৰণীয়া সেতু উদ্বোধন কৰা হৈছে।

স্বাস্থ্যখণ্ডতো কেইবাটাও উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতিৰ কথা চৰকাৰে উল্লেখ কৰিছে। অসমৰ মাতৃ মৃত্যুৰ হাৰ ৮৪লৈ হ্ৰাস পোৱাৰ লগতে ৭৫টা কেন্দ্ৰত ৮৫ হাজাৰতকৈ অধিক বিনামূলীয়া হেম'ডায়েলাইছিছ সেৱা প্ৰদান কৰা হৈছে। প্ৰায় ২.৯৪ লাখ কিশোৰীক এইচপিভি টিকা প্ৰদান কৰা হৈছে। প্ৰযুক্তি আৰু বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত



অসমৰ প্ৰথম জিপিইউ-ভিত্তিক স্বতন্ত্ৰ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা আন্তঃগাঁথনি আৰু 'অসম ছ'ৰ্চ ট্ৰেচ এআই' প্লেটফৰ্ম মুকলি কৰা হৈছে। 'এডভাণ্টেজ অসম'ৰ প্ৰায় ৩.১০ লাখ কোটি টকাৰ বিনিয়োগ প্ৰকল্প উন্নত ৰূপায়ণ পৰ্যায়ত প্ৰৱেশ কৰিছে।

নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ৬১ লাখতকৈ অধিক স্মাৰ্ট মিটাৰ স্থাপন কৰা হৈছে। পিএম সূৰ্য ঘৰ আঁচনিৰ অধীনত ১.৭০ লাখতকৈ অধিক ছাদৰ সৌৰ শক্তি ব্যৱস্থা স্থাপনেৰে অসমে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সপ্তম স্থান লাভ কৰিছে। পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত

'এক পেড় মা কে নাম' অভিযানত এক কোটিৰো অধিক গছপুলি ৰোপণ কৰা হৈছে। সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰিমাণে ২,৩৬২ হেক্টৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে।

বান পৰিস্থিতি মোকাবিলাত ৩১,৭০০ৰো অধিক বানপীড়িত লোকক সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে। সাহায্য শিবিৰ, বিতৰণ কেন্দ্ৰ, আৰ্থিক সাহায্য আৰু বানৰ পাছৰ স্বাস্থ্য শিবিৰৰ ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰা হৈছে।

ইয়াৰ উপৰি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি ৰাজ্যৰ প্ৰথমটো বিশেষ নিচাজাতীয় দ্ৰব্য দাহনাগাৰ উদ্বোধন কৰাৰ লগতে জন্ম কৰা কোটি কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় দ্ৰব্য ধ্বংস কৰা হৈছে।

জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কয় যে চৰকাৰৰ প্ৰথম ১০০ দিন কেৱল সংখ্যাৰ হিচাপ নহয়; ইয়াৰ সৈতে মাতৃ, কৃষক, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, ৰোগী, বানপীড়িত পৰিয়াল আৰু নতুন উদ্যোগীসকলৰ জীৱনৰ সৈতে জড়িত পৰিৱৰ্তনৰ কথাও জড়িত হৈ আছে।

সীমান্ত উন্নয়ন এতিয়া চৰকাৰৰ সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ : কিৰেণ ৰিজিজু

জন জন বিচাৰ

...নতুন দিল্লী

দেশৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহৰ উন্নয়ন এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ "সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ" বুলি উল্লেখ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্ত অঞ্চলত নতুনকৈ চীনা সেনাৰ অনুপ্ৰৱেশৰ দাবী নাকচ কৰি তেওঁ কয় যে কৌশলগতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ সীমান্ত অঞ্চলসমূহত আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কাম দ্ৰুতগতিত আগবঢ়াই নিয়া হৈছে।

অৰুণাচল পশ্চিম লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ ৰিজিজুৱে ছটিয়েল মিডিয়াত প্ৰকাশ কৰা বক্তব্যত কয় যে পূৰ্বৰ সময়ছোৱাত সীমান্ত অঞ্চলৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নক পৰ্যাপ্ত গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাছিল। বৰ্তমান চৰকাৰে পথ, যোগাযোগ ব্যৱস্থা আৰু অন্যান্য আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ জৰিয়তে সীমান্ত অঞ্চলসমূহ শক্তিশালী কৰাত বিশেষ গুৰুত্ব দিছে।

ৰিজিজুৱে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মাজা, গেলোমো আৰু টাকচিং অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰি আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কাম ত্বৰান্বিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱাৰ



কথাও উল্লেখ কৰে। কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ পূৰ্বৰ সীমান্ত নীতিৰ সমালোচনা কৰি ৰিজিজুৱে প্ৰাক্তন প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী এ কে এছ নীৰ ২০১৩ চনত সংসদত দিয়া বক্তব্যৰ উল্লেখ কৰে। তেওঁ দাবী কৰে যে সেই সময়ত সীমান্ত অঞ্চলৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন নকৰাৰ নীতিৰ ফলত চীনে সীমান্তৰ সিপাৰে উন্নত আন্তঃগাঁথনি গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছিল।

ইফালে, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উচ্চ সুবশিৰি অঞ্চলত চীনা সামৰিক তৎপৰতা সন্দৰ্ভত উদ্বেগ অব্যাহত থকাৰ মাজতে ৰিজিজুৱে চীনা সেনাই অৰুণাচলৰ ভিতৰত ৬০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত প্ৰৱেশ কৰাৰ দাবীক ভিত্তিহীন বুলি অভিহিত কৰিছে। তেওঁ সংবেদনশীল সীমান্ত বিষয়ক লৈ অসত্য তথ্য প্ৰচাৰ

নকৰিবলৈ আহ্বান জনায়। ৰিজিজুৱে লগতে কয় যে ভাৰত-চীন সীমান্ত সমস্যা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলৰ উদ্বেগ চৰকাৰে গুৰুত্বসহকাৰে বিবেচনা কৰিব আৰু ভাৰতীয় ভূখণ্ডৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিব।

কেন্দ্ৰীয় বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়েও স্পষ্ট কৰিছে যে ভাৰত-চীন সীমান্তত শান্তি আৰু সুস্থিৰতা বজাই ৰখাটো দুয়োখন দেশৰ সামগ্ৰিক দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। অৰুণাচলক কেন্দ্ৰ কৰি সীমান্ত পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বেগৰ মাজতে কেন্দ্ৰৰ এই বক্তব্যই সীমান্ত সুৰক্ষা আৰু আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ ওপৰত চৰকাৰে অধিক গুৰুত্ব দিয়াৰ ইংগিত বহন কৰিছে।

মিজোৰামত চিকিৎসা ক্ষেত্ৰত ঐতিহাসিক সাফল্য

জন জন বিচাৰ

...আইজল

মিজোৰামৰ চৰকাৰী জোৰাম মেডিকেল কলেজ এণ্ড হাস্পতালত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সফলভাৱে মুকলি হ'বলৈ হৃদযন্ত্ৰ অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন কৰা হৈছে। ৬৯ বছৰীয়া এগৰাকী হৃদৰোগীৰ ওপৰত সম্পন্ন হোৱা এই অস্ত্ৰোপচাৰে ৰাজ্যখনৰ চিকিৎসা সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মাইলৰ খুঁটি স্থাপন কৰিছে।

হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা অনুসৰি, হৃদৰোগীৰ ট্ৰিপল ভেছেল ডিজিজ ধৰা পৰিছিল। এই ৰোগত হৃদযন্ত্ৰলৈ তেজ যোগান ধৰা তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ধমনীত বাধাৰ সৃষ্টি হয়। প্ৰায় ছয় মাহ পূৰ্বে ৰোগীগৰাকীৰ হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত পৰীক্ষাত এই জটিল ৰোগ ধৰা পৰিছিল।

আৱাসিক হৃদ-বক্ষ অস্ত্ৰোপচাৰ বিশেষজ্ঞ ডাঃ মেৰী স্মিথথ'লুয়াংগীৰ নেতৃত্বত আৰু গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ৰ ডাঃ ইনতেখাৰ আলমৰ সহযোগত অস্ত্ৰোপচাৰটো সম্পন্ন কৰা হয়।

প্ৰায় ছয় ঘণ্টা ত্ৰিশ মিনিট ধৰি চলা জটিল ক'ৰ'নেৰী আৰ্টাৰী বাইপাছ গ্ৰাফটিং অস্ত্ৰোপচাৰৰ সময়ত হৃদযন্ত্ৰ সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি হৃদ-ফুসফুস যন্ত্ৰৰ সহায়ত ৰোগীৰ শৰীৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসিদ্ধি চলাই ৰখা হয়।

অস্ত্ৰোপচাৰত ৰোগীগৰাকীৰ ভৰিৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা ছেফেলাছ ডেইন আৰু বুকুৰ পৰা লেফট ইণ্টাৰনেল মেমোৰী আৰ্টাৰী ব্যৱহাৰ কৰি বন্ধ হৈ থকা ধমনীৰ বিকল্প ৰক্তপ্ৰবাহৰ পথ সৃষ্টি কৰা হয়।

চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিয়া মতে, অস্ত্ৰোপচাৰ সফল হৈছে আৰু বৰ্তমান ৰোগীগৰাকী আইচিইউত চিকিৎসকৰ নিবিড় পৰ্যবেক্ষণত আছে। এনাথেছিয়া বিশেষজ্ঞ, হৃদৰোগ বিশেষজ্ঞ আৰু প্ৰশিক্ষিত নাৰ্ছিং কৰ্মীৰ সহযোগিতাত এই ঐতিহাসিক অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন কৰা হয়।

মিজোৰামৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী লালবিনপাইয়ে চিকিৎসক আৰু সমগ্ৰ চিকিৎসা দলটোক অভিনন্দন জনাই এই সাফল্যক ৰাজ্যখনৰ স্বাস্থ্যগুণ সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত এক উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতি বুলি অভিহিত কৰে।

সম্পাদকীয়

পূব দিগন্তলৈ ভাৰতৰ দৃষ্টি
এতিয়া কিয় জৰুৰী

চীন পূবৰ দিশে দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে- বন্দৰ, পথ, বাণিজ্যিক কৰিডৰ, প্ৰযুক্তি আৰু সামুদ্ৰিক উপস্থিতিৰ জৰিয়তে। কিন্তু ভাৰত এতিয়াও বহু ক্ষেত্ৰত সীমান্তত চীনৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপৰ অপেক্ষাত বান্ধ। এই মানসিকতা সলনি কৰাৰ সময় আহিছে। কেৱল হিমালয় পাহাৰ বন্ধা কৰিলেই ভাৰতৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত নহয়; বংগোপসাগৰ, উত্তৰ-পূব আৰু ভাৰত মহাসাগৰকো সমান কৌশলগত গুৰুত্ব দিব লাগিব।

ভাৰতৰ উত্তৰ-পূব বহু দশক ধৰি 'সীমান্ত অঞ্চল'ৰ টেগত আবদ্ধ হৈ আছে। এই দৃষ্টিভঙ্গী এতিয়া দেশৰ বাবে ক্ষতিকৰক। উত্তৰ-পূব হৈছে দক্ষিণ-পূব এছিয়ালৈ ভাৰতৰ স্বাভাৱিক দুৱাৰ। অথচ পথ, ৰেল, সীমান্ত বাণিজ্য, লজিস্টিক আৰু ডিজিটেল সংযোগৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াও বহু কাম বাকী। অসমক যদি দিষ্টীৰ পৰা দুৰৱৰ্তী ৰাজ্য হিচাপেই দেখা হয়, তেন্তে 'এণ্ট ইষ্ট' নীতি কাগজতে সীমাবদ্ধ থাকিব।

চীনৰ শক্তি কেৱল সেনাবাহিনীত নাই; আন্তঃগাঁথনি আৰু অৰ্থনৈতিক নিৰ্ভৰতাও তাৰ অস্ত্ৰ। ভাৰতক চীনৰ প্ৰতিটো প্ৰকল্পৰ নকল কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু নিজৰ কৌশলগত সম্পদক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব লাগিব। আন্দামান-নিকোবৰ, বংগোপসাগৰ আৰু উত্তৰ-পূব

যোগাযোগ ব্যৱস্থাক জাতীয় নিৰাপত্তাৰ কেন্দ্ৰলৈ আনিব লাগিব।

কঠিন সত্যটো হ'ল-ভাৰতৰ সমস্যা চীনৰ শক্তি নহয়, বহু সময়ত নিজৰ বীৰ গতি। সীমান্তত প্ৰতিবাদ, বৈঠক আৰু বিবৃতি যথেষ্ট নহয়।

পথ নিৰ্মাণ কৰক, বাণিজ্য বৃদ্ধি কৰক, বন্দৰ শক্তিশালী কৰক, উত্তৰ-পূবক দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ সৈতে সংযোগ কৰক। চীন যদি মানচিত্ৰ সলনি কৰাৰ বাবে দশকজোৰা পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে, ভাৰতে পাঁচ বছৰৰ ৰাজনীতিৰ উৰধ্বল উঠি পঁচিশ বছৰৰ কৌশল ৰচনা কৰিব লাগিব।

ভাৰতৰ পূব সীমান্ত নহয়-ডৰিয়াতৰ শক্তিৰ দুৱাৰ। এতিয়া চকু মেলাৰ সময়।

নীতিন নবীনৰ নতুন দলৰ ৰাজনৈতিক সংকেত

জন জন বিচাৰ

...সুজল প্ৰধান

নীতিন নবীনৰ বহু প্ৰতীক্ষিত ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ ঘোষণা অৱশেষত হ'ল। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনে সংগঠনৰ দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তত তেওঁৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় দল ঘোষণা কৰিছে। নতুন দলটোত অভিজ্ঞ নেতা, নতুন মুখ, আঞ্চলিক ভাৰসাম্য, সামাজিক সমীকৰণ আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰয়োজনীয়তাৰ মাজত এক সমন্বয় ঘটোৱাৰ চেষ্টা স্পষ্ট।

কিন্তু এই নতুন দলৰ দুটা সিদ্ধান্ত বিশেষভাৱে ৰাজনৈতিক আলোচনাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে। এটা হ'ল অমিত মালৱীক আইটি ছেলৰ মুখৰীৰ দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰোৱা আৰু আনটো হ'ল প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীক ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে বিজেপিৰ শীৰ্ষ সংগঠনে পুনৰ ঘূৰাই অনা।

আইটি আৰু ছচিয়েল মিডিয়া ছেলৰ দায়িত্ব এতিয়া ছটীশগড়ৰ দীপক স্কেন দিয়া হৈছে। আনহাতে অনিল বালুৱীৰ সংবাদ মাধ্যমৰ দায়িত্বত থাকিব। অৰ্থাৎ বিজেপিয়ে ডিজিটেল ক্ষেত্ৰত মুখ সলনি কৰিছে যদিও সংবাদ মাধ্যম পৰিচালনাৰ বৰ্তমানৰ কাঠামো অব্যাহত ৰাখিছে। এই পৰিৱৰ্তনক কেৱল সাংগঠনিক ৰদ-বদল বুলি গণ্য কৰাটো কঠিন। ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে নীতিন নবীনে ডিজিটেল আৰু ৰাজনৈতিক আখ্যানৰ যুঁজত নতুন কৌশল আৰু নতুন মুখ লৈ আগবাঢ়ি বিচাৰিছে।

স্মৃতি ইৰাণীৰ প্ৰত্যাহ্বান এই নতুন দলৰ অন্যতম ডাঙৰ ৰাজনৈতিক বাৰ্তা। তেওঁক উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। আক্ৰমণাত্মক ৰাজনৈতিক শৈলী, সংবাদীয় অভিজ্ঞতা আৰু বিৰোধীৰ বিৰুদ্ধে শব্দৰ ভূমিকা গ্ৰহণৰ বাবে পৰিচিত স্মৃতি ইৰাণীক সংগঠনৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়লৈ ঘূৰাই অনাৰ অৰ্থ হ'ল বিজেপিয়ে উত্তৰ প্ৰদেশৰ দৰে নিৰ্ণায়ক ৰাজ্যত ৰাজনৈতিক তৎপৰতাক অধিক শক্তিশালী কৰিব বিচাৰিছে।

ৰাজস্থানৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বসুন্ধৰা ৰাজে সন্ধিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপ-সভাপতি কৰা হৈছে। তেওঁৰ সৈতে তীৰ্থ সিং ৰাৱত, ৰাম মাধৱ, ৰেজয়ন্ত পণ্ডা, ডি. পুৰন্দৰেশ্বৰী, ৰেখা বাৰ্মা, বৰ্ণাবেন নৰেন্দ্ৰভাই দোশী, ডব্লু ভাৰতী প্ৰবীণ পাৰাৰ, মনপ্ৰীত সিং বাল, লাল সিং আৰ্য, এম. নাগৰাজ, অধ্যাপক



তাৰিক মনজুৰ আৰু ডঃ মণ্ডুসুৰ কৰক ৰাষ্ট্ৰীয় উপ-সভাপতিৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। ছগৰাকী মহিলা উপ-সভাপতিৰ অন্তৰ্ভুক্তিয়ে মহিলা প্ৰতিনিধিত্বৰ ক্ষেত্ৰতো বিজেপিৰ স্পষ্ট বাৰ্তা দিছে।

ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদকৰ দলত বিনোদ তাৱড়ে, সুনীল বাঞ্চল, বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱ, স্মৃতি ইৰাণী, ডঃ সত্যীশ পুনিয়া, গজেন্দ্ৰ পেটেল, হৰিশ দ্বিৱেদী আৰু সঞ্জয় ভাটিয়া অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। সংগঠনৰ ক্ষেত্ৰত বি. এল. সন্তোষ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক সংগঠন হৈ থাকিব। শিৱপ্ৰকাশ আৰু সৌদান সিংক ৰাষ্ট্ৰীয় যুটীয়া সাধাৰণ সম্পাদক সংগঠনৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। অৰ্থাৎ নীতিন নবীনে অভিজ্ঞ সাংগঠনিক ব্যৱস্থাক অক্ষুণ্ণ ৰাখি ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত নিজৰ দলটোক অধিক বিস্তৃত কৰিছে।

১৬গৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদকৰ তালিকাতো আঞ্চলিক ভাৰসাম্যৰ ছবি স্পষ্ট। কবিতা পাটীদাৰ, কে. সুৰেন্দ্ৰন, ডঃ ভোলা সিং, ডঃ প্ৰদীপ বাৰ্মা, জগদীশ দীপ্তৰভাই পেটেল, আম আদমী পাৰ্টীৰ পৰা বিজেপিলৈ অহা ডঃ সন্দীপ পাঠক, ফাফন কনিয়াক, সগীতা যাদৱ, অনিল একদী, ডঃ এম. ভেঙ্কটেশ্বৰ, মনোজ ত্ৰিা, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা, ডঃ স্বদেশ সিং, মুগাংকা দেৱ বৰ্মন, ৰোহন গুপ্তা আৰু জয় প্ৰকাশক ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক কৰা হৈছে। দক্ষিণ ভাৰত, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল, পূব ভাৰত, হিন্দী বলয় আৰু নগৰীয়া ৰাজনৈতিক পটভূমিৰ নেতাসকলক ইয়াত স্থান দিয়া হৈছে।



কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ৰ প্ৰভাৱীৰ দায়িত্বত তৰুণ চুঘা আৰু কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয় সচিব হিচাপে মহেন্দ্ৰ চাও থাৰি। উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সমন্বয়কৰ দায়িত্ব ডঃ সন্দিপ পাঠক আৰু যুটীয়া সমন্বয়কৰ দায়িত্ব ৰাজীৱ বাৰুৰক দিয়া হৈছে। সকলো মাৰ্চা আৰু কোষৰ সমন্বয়ৰ দায়িত্ব বিষ্ণু দত্তশৰ্মাক দিয়া হৈছে। খতুৰাজ সিনহা আৰু বিষ্ণু বৰ্ধন ৰেড্ডী যুটীয়া সমন্বয়ক হ'ব।

মাৰ্চাসমূহৰ নেতৃত্বতো সামাজিক আৰু নিৰ্বাচনী বিস্তাৰৰ লক্ষ্য স্পষ্ট। যুৱ মাৰ্চৰ সভাপতি ডঃ হেমাংগ যোশী, মহিলা মাৰ্চৰ সভাপতি ৰূপ কুমাৰী চৌধুৰী, অ'বিচি মাৰ্চৰ সভাপতি অমৰপাল মৌৰ্য, কৃষক মাৰ্চৰ সভাপতি বংশীলাল গুৰ্জৰ, এছচি মাৰ্চৰ সভাপতি শিৱেশ কুমাৰ ৰাম, এছচি মাৰ্চৰ সভাপতি ডঃ মামালাল ৰাৱত আৰু সংখ্যালঘু মাৰ্চৰ সভাপতি কুৰুৰ বাছিত আলীক নিযুক্তি দিয়া হৈছে।

আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পীযুষ গোৱেলক ৰাষ্ট্ৰীয় কোষাধ্যক্ষ আৰু ৰাজস্থানৰ ৰাজেশ মংগলক যুটীয়া কোষাধ্যক্ষ কৰা হৈছে। পীযুষ গোৱেলৰ প্ৰশাসনিক আৰু অৰ্থনৈতিক অভিজ্ঞতা দলৰ বিস্তাৰী পৰিচালনাত উপযোগী হ'ব পাৰে। অৱশ্যে ইয়াৰ লগে লগে 'এজন ব্যক্তি, এটা পদ' নীতিৰ প্ৰসংগও উত্থাপন হৈছে। এতিয়া লক্ষ্যগণী হ'ব যে বিজেপিয়ে পীযুষ গোৱেলক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পদ এৰিবলৈ কয় নে তেওঁ



দুয়োটা দায়িত্বত থাকে।

সামগ্ৰিকভাৱে নীতিন নবীনে গঠন কৰা নতুন দলটোৱে এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে- বিজেপিয়ে সংগঠনক কেৱল পদাধিকাৰীৰ তালিকা হিচাপে নহয়, বৰং এক সুসংগঠিত নিৰ্বাচনী যন্ত্ৰ হিচাপে অধিক শক্তিশালী কৰিব বিচাৰিছে। ৰাম মাধৱৰ কৌশলগত অভিজ্ঞতা, বসুন্ধৰা ৰাজেৰ জনভিত্তি, স্মৃতি ইৰাণীৰ আক্ৰমণাত্মক ৰাজনৈতিক শৈলী, সুনীল বাঞ্চলৰ সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা, পীযুষ গোৱেলৰ প্ৰশাসনিক দক্ষতা আৰু দক্ষিণ-পূব তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ নেতাসকলৰ আঞ্চলিক অভিজ্ঞতা দলটোৰ বাবে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সহায়ক হ'ব পাৰে।

কিন্তু প্ৰকৃত প্ৰত্যাহ্বানো ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে। ভিন্ন দক্ষতা আৰু আকাংক্ষা থকা নেতাসকলক একেটা সূতাত বান্ধি ৰখা, ৰাজ্যসমূহত গোটেই নিয়ন্ত্ৰণ কৰা, বিৰোধীৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখত ডিজিটেল আখ্যান অধিক ফলপ্ৰসূ কৰা, সংগঠন আৰু চৰকাৰৰ মাজত সমন্বয় বজাই ৰখা আৰু আগন্তুক নিৰ্বাচনত এই নিযুক্তিৰ জৰিয়তে গতি তোলা সামাজিক সমীকৰণক ব্যস্তৰ ভেটিত পৰিণত কৰা সহজ নহ'ব। নীতিন নবীনে দল বাছি লৈছে; এতিয়া এই দলটোক ফলাফল প্ৰদান কৰিব পৰা ৰাজনৈতিক শক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰাটোৱেই তেওঁৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পৰীক্ষা।

আমেৰিকাৰ ঋণৰ পাহাৰ ৪০ ট্ৰিলিয়ন ডলাৰ পাৰ

জন জন বিচাৰ

...৪ ৰাষ্ট্ৰিংটন

বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ অৰ্থনীতি আমেৰিকা এতিয়া এক গভীৰ বিস্তীৰ্ণ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন। দেশখনৰ মুঠ ৰাষ্ট্ৰীয় ঋণে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৪০ ট্ৰিলিয়ন ডলাৰৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিছে। ২০২৬ চনৰ আগষ্টত এই ঐতিহাসিক সীমা অতিক্ৰম কৰাৰ তথ্য আমেৰিকাৰ ট্ৰেজাৰী বিভাগৰ তথ্যত প্ৰকাশ পাইছে।

যোৱা এটা দশকত আমেৰিকাৰ ঋণ প্ৰায় দুগুণ হৈছে। ঋণ বৃদ্ধিৰ আঁতৰ কোনো এটা চৰকাৰকেই সম্পূৰ্ণৰূপে দায়ী কৰিব নোৱাৰি। বিগত বছৰসমূহত ব্যাপক চৰকাৰী ব্যয়, কৰ হ্ৰাস, মহামাৰীৰ সময়ৰ ব্যয়, সামাজিক সুৰক্ষা আৰু স্বাস্থ্যসেৱাৰ ব্যয় বৃদ্ধিৰ লগতে ক্ৰমাগত বাজেট ঘাটতিয়ে ঋণৰ বোজা বৃদ্ধি কৰিছে।



বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ আন এটা উদ্বেগজনক দিশ হৈছে ঋণৰ ওপৰত সুদৰ বোজা। সুদ পৰিশোধৰ ব্যয় এতিয়া আমেৰিকাৰ ফেডাৰেল বাজেটৰ অন্যতম বৃহৎ খৰচত পৰিণত হৈছে

আৰু মেডিকোৱাৰ ব্যয়কো অতিক্ৰম কৰিছে। ইয়াৰ ফলত শিক্ষা, আন্তঃগাঁথনি, জনকল্যাণ আৰু অন্যান্য ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ ব্যয় কৰাৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত চাপ বৃদ্ধি পাব পাৰে।

ইফালে ইৰানৰ সৈতে চলি থকা যুদ্ধই আমেৰিকাৰ প্ৰতিৰক্ষা ব্যয় আৰু বাজেটৰ ওপৰত নতুন চাপ সৃষ্টি কৰিছে। একে সময়তে বৃদ্ধ জনসংখ্যাৰ বাবে সামাজিক সুৰক্ষা আৰু মেডিকোৱাৰ ব্যয়ো ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে।

বিশেষজ্ঞসকলৰ আশংকা, ঋণ বৃদ্ধিৰ এই গতি অব্যাহত থাকিলে আগন্তুক বছৰসমূহত আমেৰিকাৰ ঋণৰ বোজা আৰু অধিক বৃদ্ধি পাব। ইয়াৰ প্ৰভাৱ কেৱল আমেৰিকাৰ ভিতৰতে সীমাবদ্ধ নাথাকিব; ডলাৰ, বিশ্বৰ বণ্ড বজাৰ, সুদৰ হাৰ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অৰ্থনীতিতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে।

৪০ ট্ৰিলিয়ন ডলাৰৰ ঋণ কেৱল এটা সংখ্যা নহয়-এয়া বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ বাবে এক গভীৰ সতৰ্কবাণী। আমেৰিকাই এতিয়া সামৰিক শক্তি আৰু ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱৰ সমতাৰালভাৱে বিস্তীৰ্ণ শৃংখলা বজাই ৰাখিব পাৰিবনে-সেইটোৱেই আগন্তুক দিনৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন।

আঠখন ৰাজ্যত জিলা আয়ুক্তক ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ ক্ষমতা

জন জন বিচাৰ

...৪ নতুন দিল্লী

ভাৰত চৰকাৰে নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন আনিছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে নাগৰিকত্ব স্ৰুতীয় সংগ্ৰহনীয়া নিয়ম, ২০২৬ অধিসূচনা জাৰি কৰি আঠখন ৰাজ্য আৰু দুটা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত জিলা আয়ুক্তসকলক নিৰ্দিষ্ট যোগ্য আবেদনকাৰীক ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ ক্ষমতা দিছে।

নতুন নিয়ম অনুসৰি গুজৰাট, ৰাজস্থান, পঞ্জাব, পশ্চিমবংগ, অসম,

ত্ৰিপুৰা জনজাতীয় অঞ্চল বাদ দি আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল জম্মু-কাশ্মীৰ আৰু লাডাখত জিলা আয়ুক্তই ভাৰতৰ বাহিৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা যোগ্য আবেদনকাৰীৰ নাগৰিকত্বৰ আবেদন পঞ্জীয়ন অথবা স্বাভাৱিকীকৰণৰ জৰিয়তে নিষ্পত্তি কৰিব পাৰিব।

ইয়াৰ পূৰ্বে এই দায়িত্ব অধিকাৰপ্ৰাপ্ত সমিতি আৰু জিলা পৰ্যায়ৰ সমিতিৰ হাতত আছিল। নতুন ব্যৱস্থাত এই সমিতিসমূহৰ সলনি জিলা আয়ুক্তই আবেদনকাৰীৰ যোগ্যতা আৰু উপযুক্ততা পৰীক্ষা কৰি নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত ল'ব।

চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিছে যে উক্ত

অঞ্চলসমূহৰ অধিকাৰপ্ৰাপ্ত সমিতি অথবা জিলা পৰ্যায়ৰ সমিতিৰ ওচৰত বৰ্তমান বিচাৰাধীন হৈ থকা সকলো আবেদন সংশ্লিষ্ট জিলা আয়ুক্তৰ ওচৰলৈ তাৎক্ষণিকভাৱে স্থানান্তৰ কৰিব লাগিব।

ইফালে নতুন নিয়মত আবেদনকাৰীৰ স্ব-উপস্থিতিৰ ক্ষেত্ৰতো কঠোৰতা আৰোপ কৰা হৈছে। আবেদনত স্বাক্ষৰ কৰা আৰু ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি আনুগত্যৰ শপত গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত সুযোগ লাভ কৰাৰ পিছতো যদি কোনো আবেদনকাৰী নিজে উপস্থিত নহয়, তেন্তে জিলা আয়ুক্তই আবেদনখন নাকচ কৰিব পাৰিব।

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পূৰ্বে জাৰি কৰা সংশ্লিষ্ট আদেশসমূহো বাতিল কৰিছে। অৱশ্যে বাতিলৰ পূৰ্বে সম্পন্ন হোৱা বা সম্পন্ন নোহোৱা কিছুমান কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্দিষ্ট ব্যতিক্ৰম ৰখা হৈছে।

নতুন ব্যৱস্থাৰ লক্ষ্য হৈছে নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া অধিক প্ৰত্যক্ষ, জবাবদিহিমূলক আৰু কঠোৰ পৰীক্ষা-নিৰীক্ষাৰ অধীন কৰা। বিশেষকৈ অসম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই সিদ্ধান্তৰ গুৰুত্ব অধিক, কিয়নো অবৈধ প্ৰব্ৰজন আৰু নাগৰিকত্বৰ বিষয়টো এই দুয়োখন ৰাজ্যতে দীৰ্ঘদিন ধৰি সংবেদনশীল ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক বিষয় হৈ আহিছে।

মহাৰাষ্ট্ৰত ডেৰ লাখ অমৰাঠী চালকে শিকিলে মাৰাঠী

জন জন বিচাৰ

...৪ মুম্বাই

মহাৰাষ্ট্ৰত বাণিজ্যিক যাত্ৰীবাহী বাহনৰ চালকসকলৰ বাবে মাৰাঠী ভাষাৰ মৌলিক জ্ঞান বাধ্যতামূলক কৰাৰ পিছত ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক পৰীক্ষা অভিযান আৰম্ভ হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ তথ্য অনুসৰি, প্ৰায় ডেৰ লাখ মাৰাঠী ভাষা নকোৱা চালকে মাৰাঠী ভাষাৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰ মাজতে প্ৰায় ৭.৭৫০জন চালক পৰীক্ষাত অনুত্তীৰ্ণ হোৱাত তেওঁলোকক পুনৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব।

মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰী প্ৰতাপ সৰনায়েকে জানিবলৈ দিয়া মতে, বৃহৎসংখ্যক আৰম্ভ হোৱা পৰীক্ষা আৰু পৰিদৰ্শন অভিযানৰ প্ৰথম দিনাই ৰাজ্যখনত ৮,২১৭জন চালকক পৰীক্ষা কৰা হয়। ইয়াৰে মুম্বাই মহানগৰ অঞ্চলৰ ৩,৯৯৫জন চালক আছিল। মুম্বাই অঞ্চলত ৬০৪জন চালকক মাৰাঠী ভাষাৰ প্ৰয়োজনীয় জ্ঞান নথকাৰ কথা পোহৰলৈ আহে।



ৰাজ্যখনৰ আন অঞ্চলত ৪,২২২জন চালকক পৰীক্ষা কৰা হয় আৰু ইয়াৰে ৬৬৪জনক মাৰাঠী ভাষাৰ পৰ্যাপ্ত জ্ঞান নথকাৰ বাবে জননী জাৰি কৰা হয়। পৰিবহণ বিভাগে জনোৱা মতে, সমগ্ৰ পৰিদৰ্শন অভিযান ৩০ ছেপ্টেম্বৰলৈ

চলিব। চৰকাৰে মাৰাঠী নোকেৱা চালকসকলৰ বাবে বিশেষ ভাষা শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰমো আৰম্ভ কৰিছে। চালকসকলক ৰাজ্যখনৰ মুখ্য ভাষাৰ মৌলিক জ্ঞান আহৰণৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট সময় দিয়া হৈছে। এই সময়সীমাৰ ভিতৰত প্ৰয়োজনীয় জ্ঞান

আহৰণ কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকৰ চালকৰ বেজ তিনিমাহৰ বাবে নিলম্বন কৰা হ'ব পাৰে।

বৃহৎসংখ্যক পৰীক্ষাত চালকসকলক ৰছটা প্ৰশ্ন সোধা হয়। চৰকাৰৰ যুক্তি অনুসৰি, মাৰাঠী ভাষাৰ মৌলিক জ্ঞান কেৱল নিয়ম পালন কৰাৰ বিষয় নহয়; যাত্ৰীসকলৰ সৈতে যোগাযোগ, তেওঁলোকৰ সুবিধা আৰু জৰুৰী পৰিস্থিতিত নিৰাপত্তাৰ বাবেও ভাষাজ্ঞান গুৰুত্বপূৰ্ণ। এই সিদ্ধান্তক লৈ ভাষা আৰু কৰ্মসংস্থাপনৰ অধিকাৰক কেন্দ্ৰ কৰি বিতৰ্কৰ সম্ভাৱনাও সৃষ্টি হৈছে। একে সময়তে চৰকাৰৰ বক্তব্য-মহাৰাষ্ট্ৰত যাত্ৰীবাহী বাহন চলোৱা চালকসকলে যাত্ৰীসকলৰ সৈতে পৰ্যায়মত যোগাযোগ স্থাপন কৰিব পৰাকৈ স্থানীয় ভাষাৰ জ্ঞান থকাটো জনস্বার্থৰ সৈতে জড়িত।

ভাষা শিক্ষাক উৎসাহিত কৰা আৰু ভাষাৰ নামত জীৱিকাৰ ওপৰত অতিৰিক্ত চাপ সৃষ্টি নকৰাৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰখাটোৱেই এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ বাবে মূল প্ৰত্যাহ্বান।

মনোজ বাজপেয়ীৰ ৰূপত মহাত্মা গান্ধী: 'গান্ধী এণ্ড মাই মাদাৰ'-ত স্বাধীনতাৰ অন্তিম দিনৰ এক অনন্য কাহিনী

জন জন বিচাৰ
...নতুন দিল্লী

ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰত মহাত্মা গান্ধীৰ চৰিত্ৰ নতুনকৈ ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে বলীউডৰ অন্যতম শক্তিশালী অভিনেতা মনোজ বাজপেয়ী। পৰিচালক সুধীৰ মিশ্ৰৰ আগন্তুক ছবি 'গান্ধী এণ্ড মাই মাদাৰ'-ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গান্ধীজীৰ চৰিত্ৰত দেখা যাব তেওঁক। ছবিখনৰ কাহিনীৰ কেন্দ্ৰত থাকিব স্বাধীনতাৰ সময়ছোৱাত মহাত্মা গান্ধীৰ জীৱনৰ অন্তিম ২১ দিন-এনে এটা সময়, যাৰ বহু মানৱীয় আৰু অন্তৰংগ দিশ সাধাৰণতে আলোচনাৰ কেন্দ্ৰলৈ নাহে।

ইতিহাসৰ এক সংবেদনশীল অধ্যায়

'গান্ধী এণ্ড মাই মাদাৰ' কেৱল এখন ঐতিহাসিক ছবি নহয়; ই ইতিহাসৰ মাজেৰে মানুহ গান্ধীক বিচাৰি চোৱাৰ এক প্ৰয়াস। স্বাধীনতাৰ উত্তাল পৰিৱেশ, সামাজিক অস্থিৰতা আৰু বিভাজনৰ যন্ত্ৰণাৰ মাজত গান্ধীজীৰ চিন্তা, দ্বন্দ্ব আৰু মানৱীয় অনুভূতিক ছবিখনে কেনেদৰে উপস্থাপন কৰে, সেয়া হ'ব ছবিখনৰ অন্যতম আকৰ্ষণ।

পৰিচালনাৰ দায়িত্বত আছে বহু চৰ্চিত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা সুধীৰ মিশ্ৰ। 'হাজাৰোঁ খঞ্জৰাহিনী এটা', 'পাৰাডী' আৰু 'ইছ ৰাত কী সুবহ নহী'ৰ দৰে ছবিৰে নিজস্ব পৰিচয় গঢ়ি তোলা মিশ্ৰৰ বাবে এই প্ৰকল্প বিশেষ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। দীৰ্ঘদিনৰ পিছত তেওঁৰ এই ছবি ডাঙৰ পৰ্দাত মুক্তিৰ বাবে সাজু হোৱাটোও চলচ্চিত্ৰপ্ৰেমীৰ বাবে উৎসাহৰ বিষয়।

গান্ধীৰ চৰিত্ৰত মনোজ বাজপেয়ী

মনোজ বাজপেয়ীৰ অভিনয়ৰ বিশেষত্ব হৈছে চৰিত্ৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই তাৰ মানসিক জগতখনক জীৱন্ত কৰি তোলা। সেয়েহে তেওঁৰ গান্ধী ৰূপে আত্মপ্ৰকাশে ছবিখনক লৈ আগ্ৰহ আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰিছে।

গান্ধীজীৰ দৰে ঐতিহাসিক আৰু বিশ্বজনীন ব্যক্তিত্বক পৰ্দাত উপস্থাপন কৰাটো কোনো অভিনেতাৰ বাবেই সহজ কাম নহয়। কেৱল বাহ্যিক ৰূপ সাদৃশ্যই নহয়, তেওঁৰ চিন্তা, কণ্ঠস্বৰ, দেহভাংগী, সংযম আৰু মানসিক দৃঢ়তাকো বিশ্বাসযোগ্যভাৱে ফুটাই তুলিব লাগিব। মনোজ বাজপেয়ীৰ অভিনয় ক্ষমতাই সেই প্ৰত্যাহ্বানক কিদৰে গ্ৰহণ কৰে, সেয়া হ'ব ছবিখনৰ অন্যতম কেঁচুহলৰ বিষয়।



ছবিখনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত থাকিব বিশিষ্ট অভিনেতা সৌৰভ শুক্লাও।

'মা', 'পুত্ৰ' আৰু গান্ধীক লৈ এখন ছবি

ছবিখনৰ নামেই কাহিনীটোৰ এক আকৰ্ষণীয় দিশৰ ইংগিত দিয়ে- 'গান্ধী এণ্ড মাই মাদাৰ'। পৰিচালক সুধীৰ মিশ্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে, কাহিনীটো এগৰাকী মাতৃ আৰু তেওঁৰ পুত্ৰক কেন্দ্ৰ কৰি আগবাঢ়ে। মাতৃগৰাকীয়ে পুত্ৰক গান্ধীক লৈ এখন ছবি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ কয়। কিন্তু ছবিখন নিৰ্মাণৰ যাত্ৰাত মতভেদ, প্ৰশ্ন আৰু বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীৰ সংঘাত সৃষ্টি হয়।

অৰ্থাৎ, ছবিখনত কেৱল গান্ধীৰ জীৱনেই নহয়, গান্ধীক লৈ আজিৰ সমাজৰ প্ৰশ্ন, মতামত আৰু ব্যক্তিগত উপলব্ধিৰো প্ৰতিফলন ঘটিব পাৰে। ইতিহাস আৰু ব্যক্তিগত জীৱনৰ এই সংযোগেই ছবিখনক এক বেলেগ মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে।

অভিজ্ঞ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাৰ সমাহাৰ

ছবিখন প্ৰযোজনা কৰিছে অনুভৱ সিনহা আৰু নৰেন্দ্ৰ হিৰাৱতে। অনুভৱ সিনহাৰ 'বনাৰস মিডিয়া বকছ'ৰ প্ৰযোজনাত নিৰ্মিত এই ছবিখন এনএইচ ষ্টুডিঅ'ছ-এ উপস্থাপন কৰিব।

সুধীৰ মিশ্ৰ আৰু মনোজ বাজপেয়ী-দুয়োগৰাকী শিল্পীৰ সৃষ্টিশীল শক্তিৰ মিলনে ছবিখনক লৈ ইতিমধ্যে যথেষ্ট প্ৰত্যাশা সৃষ্টি কৰিছে। তাৰ সৈতে অভিজ্ঞ প্ৰযোজক অনুভৱ সিনহাৰ সংযোজনেও প্ৰকল্পটোক অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰি তুলিছে।

গান্ধীক নতুন দৃষ্টিৰে চোৱাৰ সুযোগ

মহাত্মা গান্ধী ভাৰতীয় ইতিহাসৰ এক অমোচনীয় অধ্যায়। তেওঁৰ জীৱনক লৈ অসংখ্য গ্ৰন্থ, তথ্যচিত্ৰ আৰু চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ হৈছে। তথাপি ইতিহাসৰ অন্তিম কেইটামান দিনৰ মানৱীয় দিশক কেন্দ্ৰ কৰি এখন নতুন কাহিনী কোৱাৰ প্ৰয়াসে 'গান্ধী এণ্ড মাই মাদাৰ'ক পৃথক কৰি তুলিব পাৰে।

মনোজ বাজপেয়ীৰ অভিনয়, সুধীৰ মিশ্ৰৰ পৰিচালনা আৰু স্বাধীনতাৰ অন্তিম অধ্যায়ৰ পটভূমি-এই তিনিটা উপাদানে ছবিখনক লৈ আগ্ৰহ সৃষ্টি কৰিছে। এতিয়া অপেক্ষা মাথোঁ পৰ্দাত সেই 'মানুহ গান্ধী'ক কিমান গভীৰতাৰে উপস্থাপন কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে।

GAURANSHI INDUSTRIES

Purity in Every Drop, Nature in Every Product.

100% NATURAL

- NO ADDITIVES
- BOOSTS IMMUNITY
- RICH IN ANTIOXIDANTS
- ECO FRIENDLY

TEA

NAME	MAKHANA (FOX NUT SUPERFOOD)	ASSAM CTC TEA	ASSAM CTC TEA
SIZE	200gm	250gm	100gm

HONEY

NAME	MORINGA HONEY	TULSI HONEY
SIZE	200gm	200gm

NAME	MUSTARD HONEY	LITCHI HONEY	WILD FOREST HONEY
SIZE	200gm	200gm	200gm

RAW & UNPROCESSED

PURE & NATURAL

DIRECTLY FROM OUR FARMS

TRUSTED BY THOUSANDS

3rd Floor, IIT Road, Jayguru, Amingaon, Kamrup, Assam - 781031, India

Contact : +91-88224 20619

E-Mail : gauranshiind@gmail.com
www.gauranshiindustries.com



VOICE OF ALL, FOR ALL

WEEKLY

15

JAN JAN VICHAR

Guwahati, Friday, 21 August 2026



Modi Cabinet's Big Infrastructure Push

Jan Jan Vichar

... New Delhi

While political attention remained focused on the Opposition's protests and parliamentary confrontations, the Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi cleared a major infrastructure package aimed at strengthening India's rail and road network, reducing logistics costs and improving industrial connectivity.

The Cabinet approved five major rail and highway projects worth a combined Rs. 13,041 crore. Four railway multitracking projects will strengthen the high-density Howrah-Chennai network, while an 83-km four-lane highway corridor in Bihar will improve connectivity between Muzaffarpur, Sitamarhi and Sonbarsa.

The biggest railway project is the 173-km fourth line between Kharagpur and Bhadrak (Ranital), approved at a cost of Rs. 3,352 crore. Passing through West Midnapore in West Bengal and Balasore and Bhadrak in Odisha, the project will include a 564-metre bridge over the Subarnarekha along with 41 major and 169 minor bridges. It is expected to facilitate faster movement of raw materials and finished products between major steel hubs and the Paradip and



**Rs. 13,041
Crore for Rail
and Road
Projects to
Boost Freight,
Jobs and
Connectivity**

Dhamra ports.

The project is estimated to create an additional 13 million tonnes of annual freight capacity, generate logistics savings of around Rs. 466 crore a year and create nearly 59 lakh person-days of employment. It is also projected to reduce carbon dioxide emissions by about 20.86 crore kilograms annually.

Another important project is the 75-km Bhadrak-Haridaspur fourth line, costing Rs. 1,583 crore. It will strengthen the connection between steel-producing areas and the Paradip-Dhamra port complex. The project includes major bridges over the Baitarani and Brahmani rivers and is expected to add 29 million tonnes of annual freight capacity.

The Cabinet has also approved

Rs. 2,229 crore for a 90-km third and fourth line between Gummidipundi and Gudur, improving connectivity among Chennai, Vijayawada and Renigunta and strengthening access to Chennai, Kamarajar and Krishnapatnam ports.

A further Rs. 2,286 crore has been sanctioned for a 72-km third and fourth line between Cuttack and Paradip. The project will connect Paradip port more efficiently with the Kalinganagar steel cluster, Keonjhar's iron-ore mines and the Talcher coal belt.

In Bihar, the government has approved Rs. 3,591 crore for an 83-km four-lane Muzaffarpur-Sitamarhi-Sonbarsa NH-22 corridor under the Hybrid Annuity Model. The project is expected to

reduce travel time between Muzaffarpur and Sonbarsa from around two hours to nearly one hour. It will include major bridges, road-over-bridges, underpasses and a 340-metre bridge over the Bagmati.

Taken together, these projects represent more than an expansion of railway tracks and highways. They are designed to address one of the biggest challenges facing India's growth story—the cost and efficiency of moving goods. Better rail capacity, faster port connectivity, lower logistics costs and improved road infrastructure can strengthen manufacturing, agriculture, exports and regional economies.

The projects are also expected to generate substantial employment while reducing dependence on road-based freight movement and, consequently, lowering carbon emissions.

At a time when India is seeking to strengthen its position as a global manufacturing and logistics hub, the Cabinet's infrastructure decisions underline the government's emphasis on connectivity-led economic growth. The real test, however, will lie in timely execution, cost control and ensuring that these ambitious projects translate into tangible benefits for industries, businesses and ordinary citizens.

WHEN DIMAAGI NAXAL BECAME A BANNER

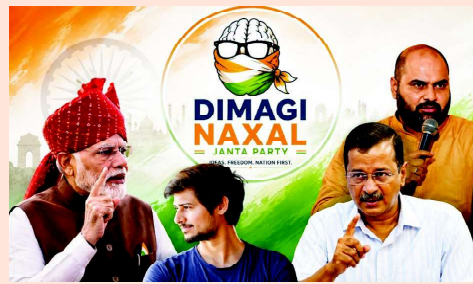
A Digital Party Rises To Challenge The Political Narrative

Jan Jan Vichar

... New Delhi

A phrase used by Prime Minister Narendra Modi in his Independence Day address has triggered an unexpected wave of activity on social media. The term 'Dimaagi Naxal' (intellectual Naxal) has now become the basis for a satirical digital initiative calling itself the 'Dimaagi Naxal Janata Party' (DNJP).

The development comes shortly after the emergence of the 'Cock-



roach Janata Party' (CJP) on social media, which reportedly attracted millions of followers within a short period. The new digital initiative is similarly being presented as a political satire

and a platform for questioning those in power.

A Digital Party, Not a Political Party

The DNJP is not a political party recognised by the Election Commission of

India. Its presence is primarily on social media, where it has reportedly attracted more than one lakh followers within 24 hours and crossed two lakh in the following days.

Its stated slogan is 'Think, Research, Question.' The initiative says its central principle is simple: irrespective of which party is in power, citizens should have the freedom to ask questions.

The platform claims that it is neither Congress, AAP, Samajwadi Party nor any other established political

organisation. It also distances itself from the earlier Cockroach Janata Party while saying that people who question authority should not necessarily consider one another political enemies.

How Did the Controversy Begin?

In his August 15 address from the Red Fort, Prime Minister Modi referred to people he described as 'dimaagi naxal'—those who, according to him, may seek to create social unrest

Continued on Page 16

Congress Failed Kaziranga : Pijush

Jan Jan Vichar

...Diphu

Assam Agriculture Minister and Guardian Minister of Karbi Anglong Pijush Hazarika launched a sharp attack on the Congress on Wednesday, accusing the Opposition party of failing to protect Kaziranga National Park and its iconic one-horned rhinoceros during its earlier tenure.

Speaking in Diphu, Hazarika said the Congress was now raising questions

over Kaziranga's protection despite what he described as its poor record on wildlife conservation.

"The Congress, which killed rhinos and destroyed Kaziranga, is now talking about protecting Kaziranga," Hazarika said.

He also took a swipe at Congress leaders over their understanding of environmental regulations, questioning whether they knew the distinction between an Eco-Sensitive Zone and an economic-related terminology.



The minister challenged the Opposition to explain its past record on rhino conservation and questioned what form of agitation it proposed to undertake over the Kaziranga issue.

Hazarika was in Diphu to attend several official and agricultural programmes. He chaired a review meeting with senior officials of the Agriculture, Irrigation and other departments at the Kazir Ronghangpi Guest House.

Later, addressing an agriculture industry programme at Sertalin Auditorium, he highlighted various government-backed agricultural loan schemes and urged farmers in the hill districts to make

greater use of them to strengthen livelihoods and achieve economic self-reliance.

The minister announced that development projects worth at least Rs. 400 crore would be undertaken in Karbi Anglong and West Karbi Anglong over the next five years. He further announced plans to plant five lakh fruit-bearing saplings annually in each of the five Assembly constituencies across the two hill districts.

Dhopalia Sarbajonin Durga Puja Committee Forms New 51-Member Panel

Jan Jan Vichar

...Guwahati

The Dhopalia Sarbajonin Durga Puja Committee has constituted a new 51-member organising committee for the 29th edition of its annual Durga Puja celebrations. The decision was taken at a general meeting held at the premises of Jyotikuchi Primary School to discuss preparations for the upcoming festival.

The meeting was chaired by committee president Munindra Deka (Moon). General Secretary Hemanta Bey explained the objectives of the meeting and presented the income and expenditure statement of last year's celebration. Members present at the meeting offered several suggestions aimed at making this year's festivities more organised and grand.

New office-bearers appointed

Tarun Kranti Ghosh has been appointed Executive President, while Hemanta Bey will continue as General Secretary and Pankaj

- Six-day Durga Puja from October 16–21
- All-Assam Aarti Competition on October 19
- Women Dhaki troupe to be major attraction

Biswas has been entrusted with the responsibility of Treasurer.

Union Minister Sarbananda Sonowal has been appointed as Chief Patron and former Rajya Sabha MP Bhubaneswar Kalita have been appointed Chief Advisor. Guwahati MP Bijuli Kalita Medhi, Dispur MLA Pradyut Bordoloi, former West Guwahati MLA and AMTRON Chairman Ramendra Narayan Kalita, Guwahati Municipal Corporation Mayor Mrigen Sarania, Deputy Mayor Smita Roy, and Manuram Tumung have been appointed advisers.

Six-day celebrations from October 16

The committee said the Durga Puja celebrations will be held from October 16 to October 21, followed by Sri Sri Lakshmi Puja on October 25. As part of the 29th-year celebrations, an All-Assam-

level Aarti Competition will be organised on October 19 (Ashtami). The winners will receive cash prizes of Rs. 7,000, Rs. 5,000 and Rs. 3,000 respectively.

Women Dhaki troupe from West Bengal to perform

A major attraction of this year's celebrations will be a women's Dhaki troupe from Maslandapur in North 24 Parganas, West Bengal, led by Padma Shri awardee Gokul Chandra Das.

On October 18 (Saptami), a special performance titled 'Mahila Nagara' will be presented by Anamika Kalita of Ghorasapar, Nalbari district.

The committee has appealed to devotees and residents to participate in large numbers in the Durga Puja and Lakshmi Puja programmes and extend their cooperation to make the 29th-year celebrations a grand success.

GUNPOINT ROBBERY

Guwahati: Security concerns for jewellery traders have once again come under the spotlight after a jewellery shop owner was allegedly robbed at gunpoint in Lal Ganesh, Guwahati, on August 8. The incident came to light on Wednesday, nearly 11 days after the alleged robbery.

According to information available, the businessman was returning home at around 10.30 pm after closing his jewellery shop when unidentified assailants allegedly intercepted him near his residence. The attackers reportedly snatched a bag he was carrying, which contained cash and gold ornaments worth several lakh rupees.

The incident took a serious turn when the assailants allegedly fired a shot into the air before escaping with the valuables. The use of a firearm has raised fresh questions over the safety of traders handling cash and precious metals in the city.

The Dispur Police are reportedly investigating the case and have yet to identify the perpetrators or make a breakthrough. The exact value of the stolen cash and jewellery has also not been officially ascertained.

Continued from page 15

When Dimaagi Naxal...

through ideology even after the country has achieved significant success against armed Naxalism. The remark quickly became a subject of political debate and social-media reactions. Opposition leaders criticised the terminology, while BJP leaders defended the Prime Minister's statement. Congress leader P. Chidambaram and other opposition figures reacted sharply, while BJP spokesperson Sudhanshu Trivedi sought to explain whom the party considers to fall within the description.

The Politics of Viral Labels

The rise of DNJP and CJP highlights a growing phenomenon in Indian politics: political statements are increasingly being transformed into digital identities, memes and online campaigns.

The DNJP's online manifesto emphasises questioning governments regardless of political affiliation. It says it has no conventional flag, fixed spokesperson or single public face, presenting itself instead as a decentralised digital initiative.

Whether such online movements translate into sustained political influence remains uncertain. But their rapid growth demonstrates the enormous power of social media to convert a

political phrase into a nationwide conversation.

The real story may not be the 'party' itself, but the changing language of political resistance. In the digital age, a controversial label can quickly be turned into a badge of identity, satire or protest. The emergence of DNJP shows that young and politically engaged social-media users are increasingly responding to political rhetoric not merely through traditional protests, but through humour, branding and viral campaigns. From 'Cockroach' to 'Dimaagi Naxal', Indian political discourse appears to be entering an era where one sentence can create an entire digital movement.

Manipur's NRC Before Census Demand Deepens

Jan Jan Vichar

...Imphal

Manipur's demand for a National Register of Citizens (NRC) before the Census has moved beyond an administrative debate, emerging as a major political and social issue with implications for identity, land, demography and representation.

Chief Minister Yumnam Khemchand Singh on Wednesday reiterated his government's support for conducting the NRC before the Census, recalling that the state Assembly had already passed a resolution on the issue in 2022. At the same time, he appealed to the Meitei, Kuki and Naga communities to rebuild trust and warned against blaming an entire community for the actions of a few individuals.

The Chief Minister's remarks came as Manipur witnessed the second day of a 48-hour general strike called by the Campaign for Just and Fair Delimitation (JFD). Markets remained closed and educational institutions shut across several valley districts, while protests, road blockades and clashes with security personnel were reported from multiple locations.

1951 proposed as NRC base year

The Joint Tribes Council Manipur (JTCM) has demanded that the NRC be implemented using 1951 as the base year to identify bona fide citizens and detect illegal immigrants. It has also called for postponing both the Census and delimitation exercise until the NRC process is completed.

The council cited concerns over alleged continued influx across the international border and its possible impact on the demographic composition of the state. According to the



JTCM, the issue directly affects the identity, land, resources and political rights of indigenous communities.

The United Naga Council (UNC) and the Coordinating Committee on Manipur Integrity (COCOMI) have similarly maintained that the NRC should precede the Census and delimitation exercise. The two organisations had submitted a joint memorandum to the Prime Minister through the Governor in May 2024 seeking an NRC before any Census exercise.

Strike brings normal life to a standstill

The agitation intensified on Wednesday. At Khurai Lamlong Bazar in Imphal East, protesters blocked roads and clashed repeatedly with security forces. A security convoy was reportedly forced to turn back after protesters obstructed its movement, while a youth sustained injuries.

Protesters also burnt effigies of Chief Minister Singh and Home Minister Govindas Konthoujam. In Thoubal, protesting groups reportedly disrupted the functioning of government offices, while at Porompat, security personnel prevented protesters from entering the Census office. Road blockades were also reported from Nomeibung Ayangpali, Uripok and Airport Lines.

Government offices in Thoubal, Kakching and Bishnupur witnessed thin attendance, although the

impact was reportedly limited in several hill districts, including Churachandpur.

Census schedule adds urgency

The controversy has assumed greater significance because the self-enumeration phase of Census 2027 in Manipur began on August 17 and will continue until August 31. House-listing and housing census operations are scheduled from September 1 to 30.

Opponents argue that conducting the Census before resolving citizenship and demographic concerns could create a population baseline with long-term consequences for political representation and delimitation.

The government, however, faces a delicate balancing act: addressing concerns over illegal immigration and demographic change without allowing the issue to deepen ethnic divisions in a state already scarred by prolonged conflict.

The larger question

The present confrontation is therefore not merely about a Census exercise. It reflects a deeper crisis of confidence over who belongs to Manipur, how its population should be recorded and how future political representation should be determined.

Meanwhile, the state government has indicated that a delegation of legislators will travel to New Delhi to raise the NRC-before-Census demand with the Centre.

NEWS IN BRIEF

Retired General Criticises Ladakh Tourist's Behaviour



New Delhi: Retired Lieutenant General D.P. Pandey has criticised a 25-year-old woman tourist who was seen arguing with security personnel in Ladakh after restrictions linked to the Zojila tunnel closure. Pandey said tourists should respect security personnel, who work under difficult conditions to maintain peace and safety.

He stressed that soldiers and security personnel are also taxpayers and rejected attempts to blame or insult them for carrying out security checks. Pandey also said the incident should not be used to portray the entire Gen Z generation negatively, describing many young people as respectful and well-mannered.

The retired officer said he would even be willing to crowd-fund a month's salary for the tourist to experience service in Siachen or a similarly challenging location.

The woman later apologised for her behaviour, saying she was frustrated at the time. She expressed respect for the Indian Army and apologised to the Army, Jammu and Kashmir Police, Ladakh Police, Chief Minister Omar Abdullah and the people of the country.

SC Allows DNA Test in Matrimonial Dispute

New Delhi: The Supreme Court has ruled that a child's DNA paternity test can be ordered in matrimonial disputes, even if the child was born during the marriage, when the test is relevant to the case.

A bench of Justices M.M. Sundresh and Prasanna B. Varale upheld orders of the Pune Family Court and Bombay High Court directing a DNA test in a divorce proceeding. The husband had alleged that he was not the biological father of the child and sought the test to support his claim of marital infidelity.

The husband had earlier obtained a private DNA test, which reportedly indicated that he was not the biological father. The Supreme Court observed that the existing DNA report provided sufficient prima facie material to justify ordering a court-directed test.

The Court rejected the woman's plea opposing the test, while noting that DNA testing cannot be ordered routinely and must be considered in the context of the facts and issues involved in a matrimonial dispute.

The ruling underlines that the presumption of legitimacy of a child does not automatically prevent DNA testing when biological paternity becomes directly relevant to adjudicating a matrimonial dispute.

EDITORIAL

'100% Pure': A Misleading Promise

The latest action by the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) against '100% pure,' '100% natural' and similar claims on food products is a welcome step in protecting consumers from misleading marketing. The message is simple but important: a bold claim on a packet is not necessarily a guarantee of quality, purity or superiority.

In a market where consumers increasingly seek natural, healthy and trustworthy food, words such as '100%

pure' carry enormous influence. They can create an impression of absolute safety and excellence even when such terminology has no specific legal recognition as an official quality certification under food safety law. This is precisely where regulation becomes essential.

The decision of several companies to remove such claims from their packaging, websites and advertisements demonstrates that regulatory scrutiny can make the food industry more accountable. However, action against a few companies cannot be the end of the matter. Regular monitoring, transparent labelling and strict penalties for repeated violations are equally necessary.

Consumers, too, have a role to play. They should not judge a food product merely by attractive claims on its packaging. Ingredients, nutritional information, manufacturing details, licence or registration information and expiry dates deserve equal attention.

FSSAI's initiative should ultimately lead to a larger culture of truthful food labelling rather than clever advertising. Food is directly linked to public health, and consumers have the right to know exactly what they are buying.

The principle is clear: purity should be established by standards and evidence—not by the size of the words printed on a packet.

Why the NTA keeps failing students

—Jan Jan Vichar

... Col G. S. Batabyal (Retd)

The National Testing Agency (NTA) was created in 2018 with the promise of bringing scientific rigour, technological sophistication, and administrative neutrality to India's examination system. Eight years later, it has become a byword for recurring crises. Every examination season now carries a sense of dread. Students approach national tests not with confidence but with the fear that a leak, an error, a cancellation, or a re-test may upend months of preparation. The question confronting the country is no longer why the NTA fails occasionally, but why it fails with such disturbing regularity. The answer lies in a combination of structural weaknesses, ethical lapses, and a culture of bureaucratic impunity that has hollowed out the institution from within.

The recent sequence of failures has been particularly damaging. The cancellation of NEET-UG after a paper leak affecting more than two million aspirants, followed by the withdrawal of the UGC-NET examination due to factual errors, mistranslations, and repeated questions, has shaken public trust. Students' organisations have taken to the streets, demanding accountability and even calling for the NTA's dissolution. The government has responded by removing hundreds of subject experts, announcing multi-layered question-paper checks, and ordering a full audit of NTA processes. These steps, though necessary, do not address the deeper malaise that has made the NTA a fragile institution incapable of deliv-

ering flawless examinations.

At the heart of the problem is a chronic shortage of permanent staff. The NTA operates with a skeletal workforce and outsources critical functions to private vendors. Question-paper setting, translation, proofreading, exam-centre operations, and even technical infrastructure are handled by external agencies. This excessive dependence on outsourcing has created opaque chains of responsibility. When errors occur, no one is clearly accountable. When leaks happen, the trail often leads to intermediaries outside the NTA's direct control. Outsourcing was meant to bring flexibility; instead, it has produced fragmentation and a diffusion of responsibility that undermines the integrity of examinations.

Security failures have compounded the problem. Despite claims of encrypted transmission, GPS-tracked logistics, and biometric verification, paper leaks have become distressingly common. Investigations into recent leaks have uncovered organised networks operating through encrypted messaging platforms, selling access to question papers and facilitating cheating. The NTA's security architecture, impressive on paper, has repeatedly collapsed in practice. Each leak erodes public faith further, and each re-test imposes emotional and financial costs on students who have already endured immense pressure.

Quality control in question-paper setting has been equally defi-

cient. The UGC-NET fiasco revealed glaring errors—incorrect facts, mistranslations, and repeated questions across sets. These are not minor lapses; they reflect systemic negligence. The removal of hundreds of experts is an implicit admission that the NTA's question-paper ecosystem is broken. The absence of leadership stability has worsened matters. After the 2024 NEET controversy, the NTA func-

tioned without a full-time head for over a year, leaving the institution adrift at a time when it needed firm direction.

Yet the most corrosive factor is bureaucratic unaccountability. When examinations collapse, students suffer, ministers resign, but senior bureaucrats rarely face consequences. The recent transfer of the Education Secretary following the NET fiasco is a familiar ritual in Indian governance. Transfer is presented as action but is little more than administrative theatre. It neither investigates negligence nor punishes wrongdoing. It merely relocates responsibility. In a system where dismissal is rare and inquiry is slow, transfer becomes the preferred gesture—visible, convenient, and ultimately meaningless. It is an eye-wash that protects the powerful while offering no justice to the millions of students whose futures depend on these examinations.

The ethical environment surrounding national examinations has also deteriorated. India's exam ecosystem has spawned a parallel industry of coaching centres, paper-leak syndicates, and corrupt

intermediaries. Investigations into NEET-UG leaks have revealed organised criminal networks exploiting vulnerabilities in the system. The NTA's weaknesses have become opportunities for unethical practices that thrive in the shadows. Students, meanwhile, are left navigating an extraction machine that drains their resources while offering no guarantee of fairness.

If India is to restore trust in its examination system, reform must be structural rather than cosmetic. The NTA needs a permanent, skilled workforce capable of handling core functions internally. Outsourcing must be restricted to non-critical tasks. Security protocols must be redesigned with real-time audit trails and compartmentalised paper-setting teams insulated from external influence. An independent examination regulator should be established to audit processes, investigate failures, and publish findings. Most importantly, bureaucratic accountability must be enforced. Transfers must give way to measurable consequences. Senior officials responsible for repeated failures must face inquiry and removal where warranted. Anything less is an insult to the millions of young Indians whose futures hinge on these examinations.

The NTA's repeated failures are not accidents; they are symptoms of a structurally flawed, ethically compromised, and accountability-averse system. India cannot afford an examination body that collapses year after year. Reform must be deep, urgent, and uncompromising. Until then, students will continue to pay the price for a system that refuses to fix itself.



Jan Jan Vichar
The Student's Corner
Board Exam Focus

Continued from Vol 30

9. Morley-Minto Reforms, 1909

The Morley-Minto Reforms of 1909 introduced separate electorates for Muslims. This meant that Muslim voters could elect representatives specifically for Muslim seats. The system strengthened the idea of separate political representation and contributed to the growth of communal politics in India.

10. Repression of the Swadeshi Movement

The British government attempted to suppress the movement through:-

arrests of nationalist leaders, restrictions on public meetings, censorship, police action, restrictions on newspapers, action against students and political activists.

Despite repression, the movement strengthened Indian nationalism.

11. Annulment of the Partition – 1911

The continued opposition to the partition eventually forced the British government to reconsider its decision.

On 12 December 1911, the annulment of the Partition of Bengal was announced. Thus, Bengal was reunited. The capital of British India was also shifted from Calcutta to Delhi in 1911.

Persons

Lord Curzon

Partition of Bengal
Surendranath Banerjee
Anti-Partition Movement

Bipin Chandra Pal

Swadeshi nationalism

Aurobindo Ghosh

Revolutionary/nationalist activities

Dadabhai Naoroji

1906 Calcutta Congress

Rabindranath Tagore

National unity and

cultural mobilisation

Abanindranath Tagore

Bharat Mata

P. C. Ray

Bengal Chemicals

ASSEMB :: Class X :: Social Science :: History :: Chapter 1

Partition of Bengal (1905–1911) and the Swadeshi Movement

Important Dates

Date/Year	Event
19 July 1905	Partition of Bengal announced
16 October 1905	Partition came into effect
1905	Swadeshi and Boycott Movement developed
11 March 1906	National Council of Education established
1906	Calcutta Session of Congress; Swaraj adopted as an important goal
1906	All-India Muslim League established
1909	Morley-Minto Reforms
12 December 1911	Partition of Bengal annulled

Important Questions

A. Very Short Answer Questions – 1 Mark

- Who was the Viceroy of India at the time of the Partition of Bengal?
- In which year was Bengal partitioned?
- On which date did the Partition of Bengal come into effect?
- Who announced the Partition of Bengal?
- When was the Partition of Bengal announced?
- What was the capital of Eastern Bengal and Assam?
- What was the official reason given by the British for the Partition of Bengal?
- What was the real political objective behind the Partition of Bengal?
- What is meant by Swadeshi?
- What is meant by Boycott?
- Name two important leaders of the Anti-Partition Movement.
- When was the National Council of Education established?
- Who played an important role in the development of Bengal Chemicals?
- Who presided over the 1906 Calcutta Session of the Indian National Congress?
- When was the All-India Muslim League established?
- What were the Morley-Minto Reforms?
- What was introduced by the Morley-Minto Reforms of 1909?
- Who painted the famous Bharat Mata?
- When was the Partition of Bengal annulled?
- What was the capital of British India before it was shifted to Delhi?

B. Short Answer Questions – 2/3 Marks

- Why did the British government decide to partition Bengal?
- What were the real objectives behind the Partition of Bengal?
- Why was the Partition of Bengal opposed by the Indian nationalists?
- What was the Anti-Partition Movement?
- What is meant by the Swadeshi Movement?
- Mention three important programmes of the Swadeshi Movement.
- What was the significance of the Boycott Movement?
- How did the Swadeshi Movement promote Indian

industries?

- What was the role of national education in the Swadeshi Movement?
- Write a short note on the National Council of Education.
- What role did students play in the Swadeshi Movement?
- What role did women play in the Swadeshi Movement?
- What role did literature and art play in the Swadeshi Movement?
- What was the contribution of Rabindranath Tagore to the Swadeshi Movement?
- Why was the 1906 Calcutta Session of the Congress important?
- What was the significance of the formation of the Muslim League in 1906?
- What were the Morley-Minto Reforms of 1909?
- What were the effects of the British repression of the Swadeshi Movement?
- Why was the Partition of Bengal annulled in 1911?
- How did the Swadeshi Movement strengthen Indian nationalism?

C. Long Answer Questions – 4/5 Marks

- Discuss the causes and objectives of the Partition of Bengal in 1905.
- Describe the Anti-Partition Movement against the Partition of Bengal.
- Explain the major programmes of the Swadeshi Movement.
- "The Swadeshi Movement was more than a movement to boycott foreign goods." Explain.
- Discuss the economic, political and social significance of the Swadeshi Movement.
- Explain how the Partition of Bengal strengthened the Indian nationalist movement.
- Discuss the role of students, women, literature and education in the Swadeshi Movement.
- Explain the importance of national education during the Swadeshi Movement.
- Describe the major events from the Partition of Bengal in 1905 to its annulment in 1911.
- Explain how the British policy of Divide and Rule contributed to the growth of communal politics in India.

Devdhwani Utsav at Kamakhya Where Faith Finds Its Rhythm

Jan Jan Vichar
... Guwahati

On the Nilachal Hill, where the spiritual atmosphere of Kamakhya Temple is deeply intertwined with Assam's cultural traditions, the annual Devdhwani (Deodhani) Utsav creates a spectacle unlike any ordinary festival. Held in August alongside the worship of Goddess Manasa, the festival brings together faith, ritual, music and a distinctive tradition of devotional trance. The official Kamakhya festival calendar lists Manasa Puja and the Debaddhani Festival among the temple's August observances.

At the heart of the celebration are the Deodhas-devotees regarded within the ritual tradition as vehicles or mediums of divine power. As the beats of traditional drums intensify, the atmosphere changes dramatically. The ritual movements become increasingly energetic, and the performers enter a trance-like state that devotees associate with the presence of the deity.



The word Devdhwani is commonly explained through Deva-the deity and Dhvani-sound or utterance. In this sense, the festival represents the symbolic 'voice of the divine', expressed through the ritual performer. The tradition is closely associated with the worship of Manasa, the serpent goddess, and reflects the meeting of Shakta worship with older indigenous ritual traditions of Assam.

Calling Devdhwani merely a

dance festival would diminish its significance. Scholars describe the Kamakhya tradition as a form of ritual or shamanic performance in which the performer becomes a medium through whom devotees perceive divine presence. Historical accounts also connect the festival's development with the long religious history of Kamakhya and the worship of Manasa.

The festival generally extends over three days, corresponding to

the transition from the end of Shravan to the beginning of Bhadra. During the celebration, devotees gather at Kamakhya from different parts of Assam and beyond, turning the temple precincts into a vibrant centre of religious and cultural activity.

A living heritage of Assam

What makes Devdhwani particularly significant is its ability to preserve a cultural memory that cannot be confined to scriptures or temple architecture. It survives through rhythm, ritual, oral tradition and human participation.

In an age when many traditional practices are being reduced to performances for tourists, Devdhwani remains deeply rooted in its religious context. Its power lies precisely in that authenticity-the drums are not merely music, the movements are not merely choreography, and the gathering is not merely a spectacle.

It is a moment when myth becomes movement, faith becomes rhythm and tradition becomes a living experience.

Marwadi Kadhi: A Spicy Taste of Rajasthan Made with Besan and Curd



of Rajasthan's traditional dishes, known for its tangy, spicy and aromatic flavour. Made with gram flour (besan), curd and a blend of whole spices, this simple dish can bring the authentic taste of a Rajasthani kitchen to your dining table.

Ingredients: ¼ cup besan, 1 cup fresh or slightly sour curd, About 4 cups water, Salt, turmeric and red chilli powder to taste, 1-2 tbsp ghee, Mustard seeds, cumin and fenugreek



cinnamon, 2 cardamoms, 2-3 cloves, 4-5 black peppercorns and 1 bay leaf, Green chilli, ginger, curry leaves and a pinch of asafoetida

Easy Method : Sieve the besan and whisk it thoroughly with the curd until the mixture becomes completely smooth and lump-free. Add salt, turmeric and red chilli powder, followed by about four cups of water. Heat ghee in a pan and add mustard seeds, cumin, fenugreek and the whole

spices. Once they begin to crackle, add chopped green chilli, ginger, curry leaves and asafoetida. Sauté briefly on low heat. Slowly pour in the besan-curd mixture while stirring continuously. Keep stirring until the kadhi comes to a boil. This prevents the curd from splitting. Reduce the heat and simmer for 15-20 minutes, allowing the flavours to develop and the kadhi to thicken.

For the finishing touch, prepare a small tempering with ghee, cumin, mustard seeds, dried red chilli and a pinch of chilli powder. Pour it over the kadhi and garnish with fresh coriander.

Serve hot with steamed rice or roti for an authentic Rajasthani experience.

DS D.S. ASSOCIATES
— TAX CONSULTANTS —

TRUSTED ADVISORS

ONE-STOP SOLUTION

**ALL YOUR TAX & FINANCE
NEEDS UNDER ONE ROOF**

Expert, reliable and timely solutions for individuals, businesses & startups — handled by experienced professionals you can trust.

OUR SERVICES

✓ Income Tax Returns	✓ GST Registration & Filing
✓ Audit	✓ Accounting & Book Keeping
✓ Loans	✓ Insurance
✓ Company Registration	✓ Import & Export Compliance
✓ Trademark Registration	✓ FSSAI Registration
✓ Subsidy Related Works	✓ Documentation Services

...AND MANY MORE SERVICES

CONTACT US TODAY
E-Mail : dssalestax@gmail.com

Dhaneshwar Choudhary
70026 82705

Subhash Choudhary
84728 20656